Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 17
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शनिवार, 24 जनवरी, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

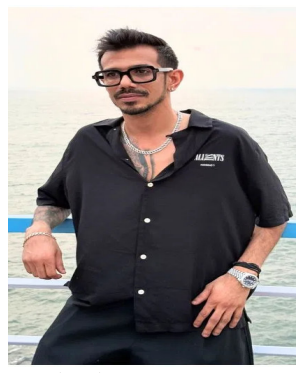

3 झरनों के प्रबंधन हेतु सतत जल उपलब्धता...

4 हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड का संघर्ष, ...

7 भारतीय का नया 'हिटमैन'! तूफानी पारी के ...

दक्षिण की पथरीली जमीन पर कमल खिलाने उतरे मोदी

केरल और तमिलनाडु में तेज हुआ सत्ता का संग्राम

नई दिल्ली। दक्षिण की पथरीली जमीन पर कमल खिलाने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल और तमिलनाडु का सघन दौरा कर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। दोनों राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक संकेतों से भरा रहा जहां विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के साथ-साथ विपक्ष पर तीखे प्रहार भी किए गए।

केरल में प्रधानमंत्री ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में भव्य रोड शो से शुरुआत की। केरल में हालिया निकाय चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन और तिरुवनंतपुरम के मेयर पद पर काबिज होने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर गया है। इसी पृष्ठभूमि में मोदी ने रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई और कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। सार्वजनिक सभा में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास और सुशासन के साथ केरल को नई दिशा दी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में सत्तारूढ़ वाम मोर्चे पर निशाना साधते हुए शबरिमला में सोना गायब होने का मुद्दा तो उठाया ही साथ ही उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के संबंधों को लेकर उस पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि वह राज्य में कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दे रही है। रैली के दौरान एक बच्चे का प्रधानमंत्री का स्केच हाथ में उठाए लंबे समय तक खड़े रहना भी चर्चा का विषय बना। मंच से मोदी का मानवीय संवाद इस दौरे की सहज तस्वीर पेश करता दिखा।

तमिलनाडु में प्रधानमंत्री का रुख अधिक आक्रामक रहा। एनडीए की रैली में उन्होंने सत्तारुढ़ द्रविड मुनेत्र कझगम यानि द्रमुक पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, महिला अपमान और तमिल संस्कृति को कमजोर करने के आरोप लगाए। मोदी ने कहा कि सत्ता की यह राह राज्य के मूल्यों और विकास को नुकसान पहुंचा रही है। इसके उलट एनडीए को उन्होंने ईमानदारी, महिला सम्मान और सांस्कृतिक गौरव पर आधारित विकल्प बताया।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तमिलनाडु की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का विस्तार से उल्लेख किया। संगम साहित्य, प्राचीन वैज्ञानिक परंपराएं, भव्य मंदिर और आधुनिक तकनीकी योगदान को उन्होंने भारत की सभ्यता की रीढ़ बताया। चेन्नई के निकट चेंगलपट्टु और मदुरांतकम की सभाओं में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य में तमिलनाडु की भूमिका निर्णायक होगी। केंद्र सरकार द्वारा पिछले ग्यारह वर्षों में राज्य के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की यूपीए सरकारों ने तमिलनाडु को अपेक्षित संसाधन नहीं दिए।

मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के शासन की सराहना करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने का श्रेय दिया और वर्तमान दौर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। पोंगल के उत्सव और एमजी रामचंद्रन की जयंती का स्मरण कर उन्होंने स्थानीय भावनाओं से जुड़ने की कोशिश की। हर मंच से उनका संदेश साफ था कि तमिलनाडु बदलाव के लिए तैयार है।

हम आपको यह भी बता दें कि केरल में राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योगपति साबु एम जैकब से मुलाकात की और उनके ट्वेंटी ट्वेंटी संगठन के एनडीए में शामिल होने का स्वागत किया। वर्कला में सिवगिरि मठ और श्री नारायण गुरु परंपरा से जुड़े संतों से भेंट कर उन्होंने सामाजिक समरसता और समानता के संदेश को भी रेखांकित किया।

देखा जाये तो दक्षिण भारत लंबे समय से भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है। केरल और तमिलनाडु में मजबूत वैचारिक परंपराएं क्षेत्रीय अस्मिता और गठबंधन राजनीति का ऐसा ताना बाना रचती रही हैं जहां राष्ट्रीय दलों के लिए जगह बनाना आसान नहीं रहा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दोहरा दौरा केवल चुनावी यात्रा नहीं बल्कि रणनीतिक दांव भी है। केरल में हालिया स्थानीय निकाय सफलता ने भाजपा को यह भरोसा दिया है कि संगठन विस्तार और विकास के एजेंडे के सहारे वह अपनी जमीन बढ़ा सकती है।

शशि थरूर का 'बगावती' तेवर!

कोच्चि में हुए अपमान के बाद कांग्रेस की हाई-लेवल बैठक से बनाई दूरी

तिरुवनन्तपुरम। केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पार्टी के दिग्गज नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने राज्य चुनाव की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है।

सूत्रों के अनुसार, थरूर का यह कदम हाल ही में कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुए 'अपमान' के प्रति उनके कड़े विरोध को दर्शाता है।

शशि थरूर कांग्रेस की अहम मीटिंग में शामिल नहीं होंगे

सूत्रों के अनुसार, यह फैसला तब लिया गया जब थरूर को कोच्चि में एक महापंचायत कार्यक्रम में 'अपमानित' महसूस हुआ, जहां पार्टी सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। अहम चर्चा मीटिंग से थरूर की गैरमौजूदगी हाई-स्टेक वाले राज्य चुनावों से पहले पार्टी के अंदरूनी मतभेद का संकेत देती है।

कांग्रेस सूत्रों ने संकेत दिया है कि वह फिलहाल कांग्रेस के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व दोनों से नाराज़ हैं, जिसके कारण उन्होंने मीटिंग में शामिल न होने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, थरूर ने अपने करीबी सहयोगियों को अपनी निराशा बताई है, और कहा है कि यह घटना पार्टी के अंदर उनके योगदान की अनदेखी के एक बड़े पैटर्न को दिखाती है।

कोच्चि इवेंट में, बैठने और बोलने के शेड्यूल को लेकर दिक्कतें आईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, थरूर को बताया गया था कि उनके बाद सिर्फ राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन बाद में दूसरे नेताओं ने भी भाषण दिया। व्यवस्थाओं को लेकर यह कन्फ्यूजन सार्वजनिक अपमान के तौर पर देखा गया, खासकर कांग्रेस में थरूर की वरिष्ठता को देखते हुए।

शुरुआती निर्देश के बावजूद, राहुल गांधी के आने के बाद कई अन्य पार्टी नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, तय प्लान से यह बदलाव थरूर की नाराजगी का कारण बना, खासकर वक्ताओं के क्रम के संबंध में प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखते हुए।

दो जगह जमानत याचिका लगाना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट बोला- यह स्वतंत्रता का दुरुपयोग, अर्जी खारिज

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपियों द्वारा समानांतर अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और हर्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला भालसावा डेयरी पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के प्रयास से संबंधित है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने हर्ष की जमानत याचिका खारिज कर उसे फटकार लगाई। वह बेंच के आह्वान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ। न्यायमूर्ति कथपालिया ने कहा कि यह स्वतंत्रता के नाम पर प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। मुझे कोई भी ऐसा कारण स्वीकार्य नहीं लगता कि आरोपी/आवेदक या उसके वकील को इन दोनों आवेदनों के दायर होने की जानकारी नहीं थी। न्यायमूर्ति कथपालिया ने आदेश दिया यह अदालत को गुमराह करने का मात्र एक प्रयास है। अग्रिम जमानत याचिका और उससे संबंधित आवेदन खारिज किए जाते हैं।

पीएम मोदी की चुप्पी पर राहुल गांधी का सवाल

यूएस टैरिफ से जा रही जॉब्स पर आखिर सरकार चुप क्यों है?

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भारत की 'कमजोर अर्थव्यवस्था' की असलियत सामने आ रही है, जिससे कपड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने नौकरियों में कटौती, कारखानों के बंद होने और ऑर्डर में कमी की चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे वाशिंगटन के साथ एक ऐसा व्यापार समझौता करें जो भारतीय श्रमिकों और व्यवसायों की रक्षा करे। हरियाणा की एक कपड़ा फैक्ट्री के अपने हालिया दौरे का वीडियो साझा करते हुए गांधी ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50इ टैरिफ और नीतिगत अनिश्चितता से कपड़ा निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक संकट में फंस गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50इ टैरिफ और अनिश्चितता से भारत के कपड़ा निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है। नौकरियों का नुकसान, कारखानों का बंद होना और ऑर्डरों में कमी आना हमारी 'बेहाल अर्थव्यवस्था' की हकीकत बन चुकी है। मोदी ने न तो कोई राहत दी है और न ही टैरिफ के बारे में कोई बात की है, जबकि 45 करोड़ से अधिक नौकरियां और लाखों व्यवसाय खतरे में हैं। मोदी जी, आप जवाबदेह हैं; कृपया इस मामले पर ध्यान दें!

गांधी ने तीखे शब्दों में मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी 'कमजोरी' को अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहिए, और सरकार से आग्रह किया कि वह अमेरिका के साथ एक ऐसे व्यापार समझौते को प्राथमिकता दे जो भारतीय हितों को सर्वोपरि रखे। भारत में वस्त्र उद्योग को दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र बताते हुए गांधी ने कहा कि शिल्प कौशल के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित यह उद्योग अब अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के साथ-साथ निर्यातकों को यूरोप में गिरती कीमतों और बांग्लादेश और चीन से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है।

जिस मुद्दे ने सत्ता दिलाई, अब उसी 'सिंगूर' से भाजपा के खिलाफ ममता शुरू करेंगी कुर्सी बचाने की लड़ाई

कोलकाता। सिंगूर और नंदीग्राम ये दो ऐसे कंधे हैं जिनपर चढ़कर ममता बनर्जी ने 2011 में उस लाल दुर्ग को ध्वस्त कर दिया, जिसपर वाम मोर्चा 34 साल से काबिज था। टाटा मोटर्स एक प्लांट लगाना चाहती थी सिंगूर में और वहां उन्होंने भूमि अधिग्रहण भी कर लिया था। लेकिन फिर जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई थी उनके साथ मिलकर ममता बनर्जी ने आंदोलन छेड़ा, विरोध प्रदर्शन किया और अंततः टाटा मोटर्स को वो जगह खाली करनी पड़ी। सिंगूर में प्रस्तावित टाटा संयंत्र ने वामपंथी दलों के गढ़ को ध्वस्त कर दिया और ममता बनर्जी को सत्ता में ला खड़ा किया। अब दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के निकट स्थित सिंगूर का बंजर इलाका, जहां टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने की परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया था, एक बार फिर बंगाल की राजनीति का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जनवरी को सिंगूर से तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रोजगार सृजन और औद्योगीकरण के क्षेत्र में उसके रिकॉर्ड पर सवाल उठाने के बाद, बंगाल की

सत्तारूढ़ पार्टी ने 28 जनवरी को वहीं अपनी रैली आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया है।

बनर्जी के लिए विधानसभा चुनावों से पहले सिंगूर लौटना अब एक बिल्कुल अलग कारण से है कि अपने प्रतिद्वंद्वियों के इस दावे का खंडन करना कि सिंगूर टीएमसी की उद्योग-विरोधी नीतियों का प्रतीक है और पार्टी के किसान-समर्थक रुख को आगे बढ़ाना है। पिछले सप्ताह पीएम मोदी ने बंगाल में 3,250 करोड़ रुपये की लागत वाली कई रेलवे और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि बंगाल में उद्योग तभी आएगा जब कानून व्यवस्था बहाल हो जाएगी। यहां हर चीज पर 'सिंडिकेट टैक्स' लगा हुआ है; भाजपा इसे खत्म करेगी, यह मोदी की गारंटी है। बंगाल में सीमा पार घुसपैठ के लगातार आरोप लगाने के अलावा, भाजपा, जो वामपंथियों की तुलना में कहीं अधिक सशक्त विरोधी है, राज्य की सीमित औद्योगिक वृद्धि को लेकर टीएमसी पर लगातार हमले कर रही है। राज्यसभा में राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार, भाजपा का दावा है कि पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई हैं।

नतीजतन, टीएमसी ने सिंगूर से ही इसका जवाब देने का फैसला किया है। बनर्जी के करीबी एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा हमारी पार्टी प्रमुख का मकसद प्रधानमंत्री मोदी को सिंगूर की धरती से ही मुंहतोड़ जवाब देना है। सिंगूर आंदोलन और हमारी पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। हमारी पार्टी प्रमुख ने सिंगूर के लिए भूख हड़ताल की थी।

मुख्यमंत्री स्टालिन की केंद्र को सीधी चुनौती

एमजीएनआरईजीए का नाम बदलने के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव को पारित कर केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि वह ग्रामीण रोजगार योजना के लिए महात्मा गांधी का नाम बरकरार रखे और वास्तविक रोजगार मांग और राज्यवार प्रदर्शन के अनुरूप पर्याप्त और निरंतर निधि आवंटन सुनिश्चित करे।

इसमें ग्रामीण नागरिकों के 'काम के अधिकार' की रक्षा पर बल दिया गया और कार्यक्रम के महत्व को महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उजागर किया गया, जिन्हें प्राथमिक लाभार्थी बताया गया। इसमें केंद्र सरकार की मौजूदा 'मनमानी से, काल्पनिक अनुमानों के आधार पर निधि आवंटन' की प्रथा की आलोचना की गई और उस पूर्व प्रणाली पर लौटने की मांग की गई जिसमें काम की वास्तविक मांग के आधार पर निधि जारी की जाती थी।

प्रस्ताव में राज्य सरकार के योगदान को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्तावित कदम पर भी आपत्ति जताई गई, जिसे विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी-राम-जी) के तहत नामित किया गया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि ऐसा कदम राज्य के वित्त पर भारी दबाव डालेगा और ग्रामीण आजीविका को नुकसान पहुंचाएगा। इस सप्ताह विधानसभा में राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण रहा, जिसके चलते प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन में इस वर्ष के पहले सत्र के दौरान पहले ही काफी हंगामा हो चुका था, जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने डीएमके सरकार द्वारा तैयार किए गए पाठ को 'गलतियों' का हवाला देते हुए पढ़ने से इनकार कर दिया और सदन से बाहर चले गए। स्टालिन ने राज्यपाल पर संवैधानिक प्रावधानों और विधायी परंपराओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो डीएमके संसद में संवैधानिक संशोधन लाने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से परामर्श करेगी।

विधानसभा से मनरेगा जारी रखने का प्रस्ताव पारित, सीएम का आरोप- वीबी-जी राम जी लोगों को कमजोर करेगी

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें केंद्र से राज्य की ग्रामीण आबादी की आजीविका की रक्षा के लिए मनरेगा को जारी रखने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पेश किया था।

केंद्र सरकार ने नया ग्रामीण रोजगार योजना 'विक्षित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी' (वीबी-जी राम जी) शुरु किया। इसका जिक्र करते हुए स्टालिन ने कहा, 'प्रस्तावित नई योजना मनरेगा की जगह लेगी। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह पूरे भारत में ग्रामीण लोगों की आजीविका, राज्यों की वित्तीय संरचना, स्थानीय निकायों की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को कमजोर करती है।'

केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं में तमिलनाडु में पहले स्थान पर है- स्टालिन

स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में चाहे वह बुनियादी ढांचा परियोजना हो या लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने की योजना, सभी पहलों को बिना किसी भेदभाव के कुशलतापूर्वक लागू किया गया। 'केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं में तमिलनाडु भारत में पहले स्थान पर है। विभिन्न मंत्रालयों से लगातार सराहना प्राप्त कर रहा है।' स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र किसी परियोजना की प्रगति के आधार पर धनराशि जारी नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार जानबूझकर धनराशि की तत्काल रिलीज से बचती है, जो तमिलनाडु के विकास के प्रति 'सौतेला' रवैया दर्शाती है।

कोई और बांध रहा था गमछा, शिवराज चौहान ने राहुल गांधी के मजदूर बनने पर कसा तंज

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम को लेकर 'नाटक' करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सांसद को इस कानून का नाम तक नहीं पता। चौहान ने ट्विटर पर राहुल गांधी के उस भाषण का एक वीडियो साझा किया, जो उन्होंने रचनात्मक कांग्रेस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एमजीएनआरईजीए श्रमिक सम्मेलन में दिया था। इस वीडियो में राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें नए अधिनियम का नाम नहीं पता।

कांग्रेस नेता पर कटाक्ष करते हुए चौहान ने लिखा कि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पर देर रात तक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और पूरा देश इस बहस को ध्यान से देख रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि इन चर्चाओं के दौरान विपक्ष के नेता अनुपस्थित थे और राहुल गांधी की इस विधेयक से

अनभिज्ञता के बावजूद कांग्रेस अब इस पर 'नाटक' कर रही है। शिवराज चौहान की पोस्ट में लिखा था, 'राहुल जी कितने ज्ञानी हैं! वीबी - श्री राम जी पर दोनों सदनों में देर रात तक घंटों चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने हर पहलू पर गंभीर बहस की। पूरा देश देख और सुन रहा था। लेकिन उस समय विपक्ष के नेता विदेश दौरे पर व्यस्त थे। अब कांग्रेस इस अधिनियम पर संघर्ष का नाटक कर रही है, जबकि विपक्ष के नेता को खुद विधेयक का नाम तक नहीं पता।

चौहान ने राहुल गांधी की हालिया सार्वजनिक उपस्थिति का मज़ाक उड़ाते हुए उन खबरों का हवाला दिया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने शारीरिक श्रम किया था। व्यंग्यात्मक टिप्पणी में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गमछा बांधने और फावड़ा चलाने का तरीका सिखाया जा रहा था। उन्होंने कांग्रेस नेता की 'तेज बुद्धि' पर भी कटाक्ष किया और दावा किया कि ऐसी बुद्धिमत्ता ही पार्टी के भविष्य के कल्याण को सुनिश्चित करेगी। मैंने सुना है कि कल राहुल जी एक दिन के लिए दिहाड़ी मजदूर भी बन गए; कोई और उन्हें गमछा बांध रहा था और खरगे जी उन्हें फावड़ा उठाना भी सिखा रहे थे। धन्य हो आप, राहुल जी, और धन्य हो आपकी 'तेज बुद्धि'! आपकी इसी अद्भुत बुद्धिमत्ता के बल पर कांग्रेस का सर्वोपरि कल्याण सुनिश्चित है।

कर्नाटक विधानसभा में 2,500 करोड़ के कथित शराब घोटाले पर हंगामा, भाजपा ने मंत्री से मांगा इस्तीफा

बंगलूरू। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को उस समय हंगामा मच गया, जब विपक्षी भाजपा ने आबकारी विभाग में 2,500 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का आरोप लगाया। भाजपा ने इस मामले को लेकर आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग की और विधानसभा के भीतर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। भाजपा की ओर से यह मुद्दा विपक्ष के नेता आर. अशोक ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब के लाइसेंस देने के बदले रिश्वत ली जा रही है और यह पैसा असम और केरल जैसे चुनाव वाले राज्यों में चुनाव खर्च के लिए भेजा जा रहा है। अशोक ने यह भी कहा कि नियमों के खिलाफ शराब के लाइसेंस की नीलामी की जा रही है।

आबकारी मंत्री ने आरोपों को किया खारिज

हालांकि, आबकारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं और वह इस तरह के दबाव से डरने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं सदन में विवाद तब और बढ़ गया, जब विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के लिए कांग्रेस विधायक एएस पोन्नन्ना को बुलाया।

भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर ने कहा कि यह प्रस्ताव इस नियम के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस मुद्दे पर बाद में किसी और नियम के तहत चर्चा की जा सकती है। लेकिन भाजपा नेता नहीं माने और जिद करते रहे कि उनकी बात पहले सुनी जाए।

इसके बाद स्पीकर ने आर. अशोक को अपनी प्रारंभिक बात रखने की अनुमति दी।

बाल ठाकरे से न मिल पाना शिवसेना छोड़ने से भी ज्यादा पीड़ादायक था : राज ठाकरे

दिव्यांश

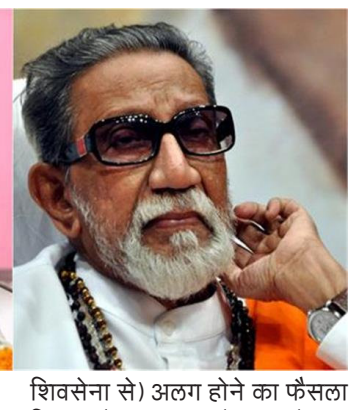

मुम्बई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना छोड़ने के बाद पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे से पहले की तरह बार-बार मुलाकात न कर पाना उनके लिए पार्टी छोड़ने से भी ज्यादा तकलीफदेह था। राज ने अपने दिवंगत चाचा को एक ऐसे पर्वत के रूप में वर्णित किया जो उनके पीछे खड़ा रहा। बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी के मौके पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के मुखपत्र 'सामना' में श्रद्धांजलि लेख में राज ने अपने ताऊ के साथ अपने गहरे रिश्ते को याद करते हुए कहा कि 2005 में पार्टी से अलग होने के परिणामों की तुलना में उनके लिए पारिवारिक घर 'मातोश्री' छोड़ने का निजी दुख कहीं अधिक बड़ा था। राज ने लिखा कि 1991 में जब वह अविभाजित शिवसेना की छात्र इकाई के प्रमुख थे और काला घोड़ा में इसने मोर्चा निकाला था, तब बाल ठाकरे ने सार्वजनिक लैंडलाइन फोन के जरिए उनका भाषण सुना था।

मनसे प्रमुख ने इस बात का भी जिक्र किया कि बचपन में एक बार वह जल गए थे तब उनके ताऊ ने दो महीने तक उनके घावों पर एंटीसेप्टिक लगाकर उन्हें साफ किया था और दो महीने तक उनकी देखभाल की थी। राज ने अपने लेख में लिखा, ''जब मैंने (अविभाजित शिवसेना से) अलग होने का फैसला किया, तो एक बात मुझे खूब परेशान करती थी कि मैं पहले की तरह अपने लोगों से बार-बार नहीं मिल पाऊंगा। मैंने अपने पिता को खो दिया था और अब मैं अपने ताऊ से भी दूर जा रहा था। यह विचार मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पार्टी छोड़ने से ज्यादा, घर (मातोश्री) छोड़ना ज्यादा तकलीफदेह था।''

राज ने बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए अविभाजित शिवसेना 2005 में छोड़ दी थी और एक साल बाद मनसे का गठन किया था। उन्होंने लिखा, ''मेरे ताऊ बालासाहेब केशव ठाकरे का मेरे बचपन और युवावस्था पर गहरा असर था। वह मेरे पीछे पर्वत की तरह खड़े रहे।'' उन्होंने बताया कि एक बार जब उनका वाहन एक ट्रक से टकराते-टकराते बचा था, तब बाल ठाकरे ने फोन करके उनका हालचाल पूछा था। अपने ताऊ से जुड़ी यादें साझा करते हुए राज ने कहा कि बाल ठाकरे पाकिस्तान के विरोधी थे लेकिन उन्होंने मेहदी हसन और गुलाम अली की गजलें सुनना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब शहर में अविभाजित शिवसेना और कम्युनिस्ट कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे तब अभिनेता-फिल्मकार राज कपूर ने शिवसेना प्रमुख से 1970 में बनी फिल्म 'मेरा नाम जोकर' के उन हिस्सों के बारे में सुझाव मांगा था जिन्हें संपादित करने की आवश्यकता थी।

मध्य रेल सतर्कता दल ने फर्जी रेलवे सतर्कता अधिकारी को पकड़ा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल सतर्कता दल ने एक महत्वपूर्ण अभियान में एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो रेलवे बोर्ड सतर्कता निरीक्षक बनकर एक रेलवे कर्मचारी से पैसे की मांग कर रहा था। रेलवे कर्मचारी की सूचना और शिकायत के आधार पर, मध्य रेल सतर्कता दल ने दिनांक 22.01.2026 को कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक अभियान चलाया और जाल बिछाया। अभियोजन के दौरान, सतर्कता दल ने हरीश कांबले को शिकायतकर्ता से 20,000/- लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी, हरीश कांबले ने रेलवे बोर्ड सतर्कता निरीक्षक बनकर शिकायतकर्ता से मुंबई के डीआरएम कार्यालय से बकाया भुगतान पास कराने के बहाने 20,000/- की मांग की थी।

इससे पहले, आरोपी हरीश कांबले ने शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 60,000/- की रिश्वत ली थी, जिसका भुगतान ऑनलाइन किया गया था, लेकिन धन हस्तांतरण कभी नहीं हुआ। आरोपी ने बकाया राशि के शीघ्र भुगतान का प्रस्ताव देकर फिर से शिकायतकर्ता से संपर्क किया। गड़बड़ी का संदेह होने पर, शिकायतकर्ता ने सतर्कता विभाग से संपर्क किया और तदनुसार एक ऑपरेशन की योजना बनाई गई। हरीश कांबले को ?20,000/- की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और आगे की कार्यवाही के लिए जीआरपी कल्याण को सौंप दिया गया।

भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 (बीएनएस) की धारा 318(2) और 319(2) के तहत धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। यह अपराध धारा 318(2) के तहत जुर्माने और 3 वर्ष तक के कारावास तथा धारा 319(2) के तहत 5 वर्ष तक के कारावास या दोनों से दंडनीय है। मध्य रेल भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है और रेलवे कर्मचारियों और जनता से सतर्क रहने तथा ऐसी किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधि की सूचना उचित अधिकारियों को देने का आग्रह करता है।

मध्य रेल के उप स्टेशन प्रबंधक और उनकी टीम ने ईमानदारी और निष्ठा की मिसाल कायम की - यात्री को खोया सामान लौटाया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

कल्याण स्थित उप स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्यिक) श्री उमेश विश्वकर्मा और उनकी टीम ने ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम करते हुए एक यात्री का खोया सामान सुरक्षित लौटाया।

दिनांक 22.01.2026 को कल्याण स्थित हेड बुकिंग क्लर्क श्री राहुल कुमार ने कार्यालय के पास एक जैकेट और बैग देखा। उन्होंने तुरंत ड्यूटी पर तैनात उप स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्यिक) श्री उमेश विश्वकर्मा को इसकी सूचना दी। उप स्टेशन प्रबंधक और ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ की उपस्थिति में स्टेशन प्रबंधक के कार्यालय में बैग खोला गया, जिसमें 12,060 रुपये नकद और 4 लाख रुपये के आभूषण मिले। आरपीएफ की मदद से यात्री का पता कसारा से लगाया गया और स्वामित्व की पुष्टि करने के बाद उप स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्यिक) श्री उमेश विश्वकर्मा ने सामान यात्री को सौंप दिया।

यात्री ने रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई, ईमानदारी और समर्पण की सराहना की।

मध्य रेल श्री विश्वकर्मा और उनकी टीम द्वारा विश्वास और सेवा के मूल्यों को बनाए रखने के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

मध्य रेल यात्रियों से अपने सामान का ध्यान रखने की अपील करता है और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में सहायता के लिए 139 डायल करने का अनुरोध करता है।

मध्य रेल पर रविवार को मेगा ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल, मुंबई मंडल रविवार, दिनांक 25.01.2026 को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर मेगा ब्लॉक परिचालित करेगा। इसका विवरण इस प्रकार हैः

मेन लाइनः

माटुंगा-मुलुंड अप और डाउन फास्ट लाइन 11.05 बजे से 15.45 बजे तक सीएसएमटी मुंबई से 10.36 बजे से 15.10 बजे तक चलने वाली डाउन फास्ट लाइन सेवाएं माटुंगा स्टेशन पर डाउन स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और माटुंगा और मुलुंड स्टेशनों के बीच अपने निर्धारित ठहरावों के अनुसार रुकेंगी और अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी। ठाणे से आगे जाने वाली फास्ट ट्रेनों को मुलुंड स्टेशन पर डाउन फास्ट लाइन पर पुनः डायवर्ट किया जाएगा।

ठाणे से सुबह 11:03 बजे से दोपहर 15:38 बजे तक चलने वाली अप फास्ट लाइन की सेवाएं मुलुंड स्टेशन पर अप

स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी। मुलुंड और माटुंगा स्टेशनों के बीच अपने ठहरावों के अनुसार रुकेंगी और पुनः माटुंगा स्टेशन पर अप फास्ट लाइन पर वापस डायवर्ट की जाएंगी तथा अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी

हार्बर लाइन

सीएसएमटी - चूनाभट्टी/बांद्रा डाउन हार्बर लाइन सुबह 11.40 बजे से दोपहर 16.40 बजे तक और चूनाभट्टी/बांद्रा-सीएसएमटी अप हार्बर लाइन सुबह 11.10 बजे से दोपहर 16.10 बजे तक

सीएसएमटी से सुबह 11.16 बजे से दोपहर 16.47 बजे तक वाशी/बेलापुर/पनवेल के लिए छूटने वाली डाउन हार्बर लाइन सेवाएँ और सीएसएमटी से सुबह 10.48 बजे से दोपहर 16.43 बजे तक बांद्रा/गोरेगांव के लिए छूटने वाली डाउन हार्बर लाइन सेवाएँ निलंबित रहेंगी।

सुबह 9.53 बजे से दोपहर 15.20 बजे तक पनवेल/बेलापुर/वाशी से सीएसएमटी के लिए छूटने वाली अप हार्बर लाइन की सेवाएँ और सुबह 10.45 बजे से शाम 17.13 बजे तक गोरेगांव/बांद्रा से सीएसएमटी के लिए छूटने वाली अप हार्बर लाइन की सेवाएँ निलंबित रहेंगी। ब्लॉक अवधि के दौरान पनवेल और कुर्ला (प्लेटफ़ॉर्म नंबर 8) के बीच 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर स्पेशल सेवाएं चलेंगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान हार्बर लाइन के यात्रियों को सुबह 10.00 बजे से शाम 18.00 बजे तक मेन लाइन और पश्चिम रेलवे के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति है। ये रखरखाव मेगा ब्लॉक बुनियादी ढाँचे के रखरखाव और संरक्षा के लिए आवश्यक हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे होने वाली असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन को सहयोग करें ।

मध्य रेल

सामग्री प्रबंधन विभाग

ई.–निविदा सूचना क्रमांक. NIT/01/26/05 दिनांक 22–जनवरी–2026

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, मध्य रैलवे निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई–निविदाएं आमंत्रित करते हैं:

क्र.	निविदा क्र.	विवरण	मात्रा	नियत तिथि
1	36261103	पोर्सिलेन 9 टन इंसुलेटर	2668 नग	12–फरवरी–26
2	36261903	पोर्सिलेन ब्रैकेट इंसुलेटर	2891 नग	12–फरवरी–26
3	27261762	फिनीशड शाफ्ट	264 नग	12–फरवरी–26
4	27264668	माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्पीडोमीटर	101 सेट	09–फरवरी–26
5	27264727	क्राउन गियर कपलिंग	58 नग	12–फरवरी–26
6	51256066A	ओवरराइडिंग स्विच 1 इन 12 और 1 इन 8.5 के लिए रनिंग कॉन्ट्रेक्ट, आरडीएसओ ड्राइंग संख्या टी–4219 और टी–4966	1300 सेट	10–फरवरी–26
7	27264678	डिस्क ब्रेक व्यवस्था के लिए स्पेयर पार्ट्स का सेट	47 सेट	09–फरवरी–26
8	38253382	एलएचबी फिएट बोगी के लिए एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम के लिए मानकीकृत ब्रेक डिस्क, आरडीएसओ ड्राइंग संख्या सीजी–15066, ऑल्ट. 1 के अनुसार और आरडीएसओ विनिर्देश संख्या आरडीएसओ/2017/सीजी–02, संशोधन 3, अप्रैल 2025	4264	10–फरवरी–26
9	41255123ए	यूटीएस थर्मल प्रिंटर/सीएएमसी के साथ	2300 नग	11–फरवरी–26
10	27263946	एम.एस. फेब्रिकेटेड इम्पेलर	225 नग	12–फरवरी–26
11	27262349	पीओएच रिप्लेसमेंट किट	50 सेट	13–फरवरी–26
12	27263673	एंड फ्रेम नॉन ड्राइविंग एंड असेंबली	57 नग	11–फरवरी–26
13	42251208	पेंटोग्राफ पूर्ण	08 नग	19–फरवरी–26
14	50254015	एसएमपीएस आधारित एकीकृत विद्युत आपूर्ति (आईपीएस) प्रणाली के लिए सीलबंद, रखरखाव–मुक्त वी आरएलए बैटरी का सेट, 60 सेल, प्रत्येक 2V/300 AH	97 सेट	18–फरवरी–26
15	50255417	आर्मर्ड 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) आरडीएसओ/एसपीएन/टीसी/110/2020, रेव–0.0	830.55 किमी	16–फरवरी–26
16	38263369	आरडीएसओ ड्राइंग संख्या आरडीएसओ/सीजी/डीआरजी/21048, ऑल्ट.3 के अनुसार और आरडीएसओ/सीजी–18005, रेव के अनुरूप, फिएट बोगियों से सुसज्जित सभी प्रकार का एलएचबी कोचों के लिए पॉ डैम्पर।	6325 नग	13–फरवरी–26
17	38263367	सभी एलएचबी कोचों के लिए प्राथमिक ऊर्ध्वाधर डैम्पर, जिनमें फिएट बोगी ड्राइंग संख्या आरडीएसओ/सीजी/डीआरजी/21047, ऑल्ट.3 लगी हो और जो आरडीएसओ/सीजी–18005, रेल–2 के अनुरूप हों	13480 नग	13–फरवरी–26
18	51256055	50 किलोग्राम (UIC) भार क्षमता वाले मोटे वेब स्विच एक्सपेंशन जॉइंट के लिए प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर	2500 सेट	18–मार्च–26

नोटः– उपरोक्त सभी निविदाएं ई–निविदाएं हैं और सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि वे अपनी बोलियां **IREPS** वेबसाइट **https://www.ireps.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें। उपर्युक्त निविदाओं और अन्य आपूर्ति निविदाओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया **IREPS** वेबसाइट पर जाएं। **848**

टिकट के लिए UTS APP डाउनलोड करे

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर पुराने पिट लाइन कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

निरस्त होने वाली ट्रेनेंः

ट्रेन संख्या 05054 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 मार्च, 2026 तक निरस्त रहेगी।

ट्रेन संख्या 05053 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 27 मार्च, 2026 तक निरस्त रहेगी।

शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनेंः

8 फरवरी, 2026 से 29 मार्च, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22921 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस बलरामपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बलरामपुर एवं गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी।

10 फरवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22922 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस बलरामपुर स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा गोरखपुर एवं बलरामपुर के बीच निरस्त रहेगी।

अस्थायी तौर पर विस्तारित ट्रेनेंः

ट्रेन संख्या 19409 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस जिसे पहले 14 फरवरी, 2026 तक थावे तक विस्तारित किया गया था, अब इसे 28 मार्च, 2026 तक थावे तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 19410 गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस जिसे पहले 16 फरवरी, 2026 तक थावे से ओरिजिनेट किया जा रहा था, अब इसे 29 मार्च, 2026 तक थावे से ओरिजिनेट किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे का रविवार को अंधेरी एवं गोरेगांव तथा माहिम एवं अंधेरी स्टेशनों के बीच जम्बो ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)।पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रैक, सिगनलिंग एवं ओवरहेड उपकरणों के रखरखाव कार्य हेतु रविवार, 25 जनवरी 2026 को जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक हार्बर लाइन पर अंधेरी एवं गोरेगांव के बीच 10.00 बजे से 15.00 बजे तक तथा माहिम-अंधेरी के बीच 11.00 बजे से 16.00 बजे तक रहेगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान मध्य रेल की सभी छत्रपति महाराज टर्मिनस-बांद्रा-छत्रपति महाराज टर्मिनस एवं छत्रपति महाराज टर्मिनस/पनवेल-गोरेगांव-छत्रपति महाराज टर्मिनस/पनवेल हार्बर लोकल सेवाएं निरस्त रहेंगी। इसके अतिरिक्त, चर्चगेट एवं गोरेगांव स्टेशनों के बीच कुछ स्लो लोकल सेवाएं भी निरस्त रहेंगी। निरस्त की गई ट्रेनों की सूची स्टेशन मास्टर के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था का कृपया ध्यान में रखकर यात्रा करें।

एल्गार परिषद मामले में दो और आरोपियों को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'समानता' के आधार पर दी जमानत

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एल्गार परिषद-माओवाद लिंक मामले के दो और आरोपियों सागर गोरखे और रमेश गैचोर को जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह कदम समानता के आधार पर उठाया, क्योंकि इस मामले के कई अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एएस. गडकरी और एससी चंदक की पीठ ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपए के जमानत बॉन्ड भरने के निर्देश दिए। गोरखे और गैचोर सितंबर 2020 से नवी मुंबई की ताजोला जेल में बंद थे।

बता दें कि सागर गोरखे और रमेश गैचोर पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) से जुड़े होने का आरोप है। जमानत के साथ कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि दोनों को हर महीने एक बार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी।

केवल एक आरोपी अब जेल में

इस आदेश के बाद अब इस आठ साल से ज्यादा पुराने मामले में गिरफ्तार 16 में से 14 लोगों को जमानत मिल चुकी है। अब केवल एक आरोपी सुरेंद्र गाडलिंग ही जेल में हैं, क्योंकि उनका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस केस में एक आरोपी फादर स्टान स्वामी, जो 84 वर्षीय पादरी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता थे, की जुलाई 2021 में जेल में ही मौत हो गई थी। वह भी जमानत का इंतजार कर रहे थे।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कई आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रहने और यह संभावना देखते हुए कि मुकदमा जल्द शुरू नहीं होगा, पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इसी कारण गोरखे और गैचोर को भी जमानत दी गई। यह मामला 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित 'एल्गार परिषद' कार्यक्रम से जुड़ा है। पुलिस का आरोप है कि इस कार्यक्रम में दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण अगले दिन पुणे के पास कोरेगांव-भीमा में हिंसा हुई थी।

पुलिस ने किया था दावा

गौरतलब है कि शुरुआत में इस केस की जांच पुणे पुलिस ने की थी। पुलिस का दावा था कि इस कार्यक्रम को माओवादियों का समर्थन मिला हुआ था। बाद में यह जांच एनआईए को सौंप दी गई। इस केस के अन्य आरोपियों में वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े, वर्नन गोंसाल्वेस, अरुण फरेरा, शोमा सेन, गौतम नवलखा, सुधीर धवले, रोना विल्सन, ज्योति जगताओ और महेश राउत शामिल हैं।

पश्चिम रेलवे

विद्युत कार्य

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/पी/बीसीटी, मुंबई सेंट्रल द्वारा निविदा सूचना संख्याः EL-81-38-201-WA-69, दिनांक 19.01.2026 आमंत्रित की जाती है। **कार्य एवं स्थानः** उद्यना न्यू गुड्स शेड इलेक्ट्रिकल - UNGA में इलेक्ट्रॉनिक इन-मोशन वेब्रिज (EIMWB) लगाने के संबंध में (पावर) का काम। **कार्य की अनुमानित लागतः** 10,97,938/- **ईएमडीः** 22,000/- **जमा करने की तिथि एवं समयः** 18.02.2026 तक, 15:00 बजे **खोलने की तिथि एवं समयः** 18.02.2026 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएँ। 1037

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

शुद्धिपत्र सूचना

निविदा सूचना संख्या BCT-25-26-295, दिनांक 13.01.2026, डीओपी 06.02.2026 के संबंध में।मौजूदा खोलने की तिथिः 06.02.2026।

संशोधित खोलने की तिथि (इस प्रकार पढ़ी जाए)ः 10.02.2026। अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। 1040

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

मानसून से पहले रखरखाव गतिविधियों की आउटसोर्सिंग

सीनियर DEE/TRS/BL, इलेक्ट्रिक लोको शेड, वलसाड, ई-टेंडर नोटिस नंबर: EL/TRS/BL/25-26/WO/04A दिनांकः 21.01.2026 आमंत्रित करता है। **काम का नाम और उसका स्थानः काम** - दो साल की अवधि के लिए सभी ELS/BL-आधारित लोकोमोटिव की मानसून से पहले रखरखाव गतिविधियों की आउटसोर्सिंग। **स्थानः** इलेक्ट्रिक लोको शेड, वेस्टर्न रेलवे, वलसाड - 396001 (गुजरात)। **काम की अनुमानित लागतः** 49,25,400/-। **ईएमडीः** 98,500/-। **जमा करने की तारीख और समयः** 11.02.2026 तक, 12:00 बजे। **खोलने की तारीख और समयः** 11.02.2026 को 12:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं 1044

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

विविध कार्य

उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे, मुंबई 400020 द्वारा ई-टेंडर संख्याः Dy.CE(C)CCG/356, दिनांक 20.01.2026 आमंत्रित किया जाता है। **कार्य का नामः** जोगेश्वर में पुल संख्या 46 का विस्तार तथा शंटिंग नेक का प्रावधान। **एनआईटी मूल्यः** 9,47,15,587.62 **ईएमडीः** 6,23,600/- **ई-बिड बंद होने की तिथिः** 03.02.2026 तक, 15:00 बजे। **ई-बिड खोलने की तिथिः** 03.02.2026 को 15:30 बजे। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएँ। 1034

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

सामग्री प्रबंधन विभाग की ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रम के संबंध में शुद्धिपत्र

जनवरी 2026 के दौरान पी.वे तथा अन्य विभिन्न स्क्रैप के लिए अतिरिक्त ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रमः कृपया इस कार्यालय की ई-नीलामी बिक्री सूचना संख्या S III/Auction Programme-1/JAN-2026 दिनांक 11/12/2026 का संदर्भ लें। उक्त सूचना के अतिरिक्त, जनवरी 2026 में पी.वे स्क्रैप सामग्री के निपटान हेतु निम्नलिखित मंडल के लिए मौजूदा कार्यक्रम के अलावा निम्न अतिरिक्त ई-नीलामी कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगाः

डिपोट	जनवरी, 2026 का अतिरिक्त ई-ऑक्शन कार्यक्रम	डिविजनल ऑफिसर इंचार्ज	संपर्क नंबर
रतलाम	27.01.2026	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक-रतलाम	07412230080 09752492750

अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया पश्चिम रेलवे के सामग्री प्रबंधन विभाग की वेबसाइट wr.indianrailways.gov.in तथा www.ireps.gov.in ई-नीलामी पोर्टल पर अवलोकन करें। 1038

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

सामग्री प्रबंधन विभाग की ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रम के संबंध में शुद्धिपत्र

जनवरी 2026 के दौरान पी.वे तथा अन्य विभिन्न स्क्रैप के लिए अतिरिक्त ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रमः कृपया इस कार्यालय की ई-नीलामी बिक्री सूचना संख्या S III/Auction Programme-1/JAN-2026 दिनांक 11/12/2026 का संदर्भ लें। उक्त सूचना के अतिरिक्त, जनवरी 2026 में पी.वे स्क्रैप सामग्री के निपटान हेतु निम्नलिखित मंडल के लिए मौजूदा कार्यक्रम के अलावा निम्न अतिरिक्त ई-नीलामी कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगाः

डिपोट	जनवरी, 2026 का अतिरिक्त ई-ऑक्शन कार्यक्रम	डिविजनल ऑफिसर इंचार्ज	संपर्क नंबर
प्रतापनगर	29.01.2026	उप. मुख्य सामग्री प्रबंधक - प्रतापनगर	0265-2658858 09724045550

अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया पश्चिम रेलवे के सामग्री प्रबंधन विभाग की वेबसाइट wr.indianrailways.gov.in तथा www.ireps.gov.in ई-नीलामी पोर्टल पर अवलोकन करें। 1045

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

झरनों के प्रबंधन हेतु सतत जल उपलब्धता आवश्यक : गणेश पाटील

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

स्वच्छ और सतत जल उपलब्ध कराने वाले झरने प्राकृतिक जल स्रोत हैं। ये झरने प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ मानव-जनित कारणों से भी प्रभावित हो रहे हैं और अनेक स्थानों पर सूखते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जल की आवश्यकता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए झरनों के पुनर्भरण, संरक्षण और सतत जल उपलब्धता के लिए ठोस प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का मृदा एवं जल संरक्षण विभाग शीघ्र ही नीति निर्धारित करेगा, ऐसा प्रतिपादन मृदा एवं जल संरक्षण सचिव श्री गणेश पाटील ने एक्सप्रेस से बातचीत में किया।

पंचगनी स्थित वसुंधरा वॉटरशेड विकास संस्था द्वारा यंत्रणा और ग्रामपरी के सहयोग से झरना प्रबंधन विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वसुंधरा वॉटरशेड विकास प्रणाली, पुणे के साथ-साथ पुणे, सातारा, कोल्हापुर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अहिल्यानगर, नाशिक और नंदुरबार जिलों से आए अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया गया।

झरनों के पुनर्जीवन और संरक्षण के लिए जागरूक होकर कार्य करना आवश्यक है। इस विषय में नई जानकारी सीखकर उसे व्यवहार में लाने, विषय में दक्ष बनने तथा प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण हेतु व्यापक जनजागरूकता निर्माण करने की अपील भी श्री पाटील ने की।

इस अवसर पर एक्वाडैम के निदेशक डॉ. हिमांशु कुलकर्णी ने महाराष्ट्र में झरनों के पुनर्स्थापन पर अपने विचार रखे और इस संबंध में नीति पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि झरने भूजल का सबसे प्राचीन स्रोत हैं और यह पर्यावरण के अनुकूल जल स्रोत होने के कारण इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सरकार, इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं, विशेषज्ञ, नाबार्ड और ग्रामीणों को संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

झरने स्वच्छ, सुरक्षित और सतत जल उपलब्ध कराने वाले प्राकृतिक स्रोत हैं। इसलिए उनका उपभोग करने के साथ-साथ उनका संरक्षण करना भी अनिवार्य है। यह केवल सरकार और प्रशासन ही नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है, ऐसा मत वसुंधरा वॉटरशेड विकास प्रणाली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर वरलाइट्स ने व्यक्त किया।

प्रशिक्षणार्थियों को झरने की संपूर्ण यात्रा समझाने के लिए सातारा जिले के जावली तालुका के रांगेघर गांव में एक जलझरने का प्रत्यक्ष अध्ययन किया गया। तामकाडा झरने की ट्रांजिट वॉक आयोजित की गई। इसमें स्रोत बिंदु से नीचे की ओर बहने वाले प्रवाह तक झरने के जल की प्राकृतिक यात्रा, जहां-जहां जल जमीन में समाहित होता है, जल प्रवाह, मार्ग, झरने की वर्तमान स्थिति, आसपास की भूवैज्ञानिक एवं भौगोलिक जानकारी, जल गुणवत्ता, स्प्रिंग बॉक्स, वॉटरशेड विकास कार्य, मानवीय हस्तक्षेप आदि सभी पहलुओं का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस दौरान एक्वाडैम के मुकेश पाटील, मृत्युंजय विचार, ग्रामपरी के दीपक जाधव और विकास जाधव ने तकनीकी जानकारी के साथ ग्रामीणों का मार्गदर्शन किया।

प्रशिक्षण की शुरुआत वसुंधरा वॉटरशेड विकास प्रणाली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, ग्रामपरी की निदेशक जयश्री राव एवं अर्चना राव के हाथों जलपूजन कर की गई। एक्वाडैम के भूवैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र में प्राकृतिक झरनों की पहचान, पंजीकरण, संरक्षण, पुनर्वास, जल की सतत उपलब्धता तथा जनभागीदारी के माध्यम से स्थायी प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

झरना प्रबंधन विषय पर आयोजित इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया। ये प्रशिक्षक महाराष्ट्र में झरना नीति के क्रियान्वयन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे।

'आप दूसरी दुनिया में नहीं रह रहे': वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, निगम अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई और नवी मुंबई की नगर निगमों के अधिकारियों को कठोर चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर उन्होंने वायु प्रदूषण कम करने के आदेशों का पालन नहीं किया, तो उनके वेतन रोक दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी भी वही प्रदूषित हवा सांस ले रहे हैं, कोई अलग दुनिया में नहीं रहते। इतना ही नहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों नगर निगमों के आयुक्तों को चेतावनी भी दी।

कोर्ट ने कहा कि अगर उन्होंने लगातार जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं किया, तो उनके वेतन रोक दिए जाएंगे। अदालत ने कहा कि पिछले साल 2023 में खुद ही (सुओ मोटु) प्रदूषण बढ़ने के मामले में कदम उठाए थे और नगर निगमों को निर्देश दिए थे कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं।

बीएमसी के वकील ने कोर्ट में दी दलील वहीं कोर्ट की फटकार के बाद बीएमसी के वकील अपनी दलील पेश की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कई निर्माण स्थलों पर काम रोकने के नोटिस जारी किए गए हैं और लगभग 600 में से 400 साइटों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग

डिवाइस लगाए गए हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस जवाब से संतोष नहीं जताया और कहा कि ये सभी कदम केवल कोर्ट के आदेशों के बाद ही उठाए गए, जबकि वर्षों तक कोई स्वयंसेवी और गंभीर प्रयास नहीं किए गए। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के डेटा की विस्तृत रिपोर्ट मांगी और बीएमसी को नवंबर 2025 से तीन महीने पहले तक का रोजाना का सेंसर डेटा जमा करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों को सख्ती से लगाई फटकार

कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर निगमों द्वारा दाखिल हलफनामों में वार्ड-वार विवरण नहीं है और इससे प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने प्रदूषण कम करने में गंभीरता से काम नहीं किया। अदालत ने साफ किया कि यह सिर्फ जांच करने का मामला नहीं है, बल्कि नगर निगमों की जिम्मेदारी है कि वे हवा को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाएं।

राज्य नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के समक्ष प्रस्तुति

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने राज्य सरकार की भूमिका प्रस्तुत की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र की नदियों को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है और 'राज्य नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण' की स्थापना की महत्वपूर्ण संकल्पना प्रस्तुत की है। राज्य की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे ने नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल से भेंट कर इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि यदि इस प्राधिकरण को स्वीकृति मिलती है, तो यह देश का पहला ऐसा प्राधिकरण होगा।

इस विशेष बैठक में पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने राज्य में चल रही जल एवं पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नदियों की स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार के सहयोग के साथ-साथ राज्य के पास अपनी स्वतंत्र व्यवस्था और नियोजन होना समय की आवश्यकता है। देश की कई नदियाँ विभिन्न राज्यों से होकर बहती हैं। यदि प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर नदी तल की स्वच्छता और पुनर्जीवन के लिए स्थानीय स्तर पर प्रभावी और सुव्यवस्थित योजनाओं को लागू करे, तो नदियों को पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त बनाने का सपना साकार हो सकता है। मंत्री मुंडे ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से भविष्य में देश नदियों की पवित्रता और उनकी प्राकृतिक स्वरूपता को बनाए रखने में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा।

केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने इस दिशा में महाराष्ट्र द्वारा उठाई गई पहल की विशेष रूप से सराहना की तथा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

इस बैठक में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) के निदेशक श्री राजेश कुमार, महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव श्रीमती जयश्री भोज, तथा केंद्र और राज्य के अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 'बिग्सी' एक अभिनव, निःशुल्क पहल – परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'बिग्सी' नामक एक अभिनव एवं पूर्णतः निःशुल्क पहल शुरू की जा रही है। यह पहल गृह विभाग एवं परिवहन विभाग के संयुक्त सहयोग से लागू की जा रही है। परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शुरू की गई यह सामाजिक जागरूकता आधारित योजना भविष्य में महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगी।

महाराष्ट्र पुलिस, मोटर परिवहन विभाग, यातायात पुलिस तथा ईटीएस 360 टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के सहयोग से मुंबई सहित पूरे राज्य में काली-पीली टैक्सियों एवं ऑटो-रिक्शाओं के लिए बिग्सी सेवा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संयुक्त परिवहन आयुक्त शैलेश कामत, उप परिवहन आयुक्त अजीत बोगारदे, मुख्य प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाटिल तथा बिग्सी के संस्थापक प्रोफेसर निरंजन भट्ट उपस्थित थे।

परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने कहा कि शहरीकरण के कारण कार्यरत महिलाओं की यात्राओं में वृद्धि हुई है और उनके परिवार सदैव उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। दिल्ली के निर्भया प्रकरण के बाद महिला सुरक्षा का विषय राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से लिया गया। इसके पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक यात्री वाहन में वाहन स्थान एवं ट्रैकिंग उपकरण तथा पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया गया।

इसी पृष्ठभूमि में सामाजिक दायित्व के तहत महिलाओं को बिना किसी आर्थिक बोझ के सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ईटीएस 360 टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के संस्थापक प्रोफेसर भट्ट एवं उनकी टीम ने एक वैकल्पिक समाधान विकसित किया। कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों, प्रशासनिक नियमों की कमी तथा तकनीकी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने इस परियोजना को आगे बढ़ाया।

विवेक भीमनवार ने बताया कि इस प्रणाली को परिवहन विभाग, पुलिस तंत्र तथा कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ एकीकृत कर लागू किया गया है।

यद्यपि यह पहल वर्तमान में स्वैच्छिक है, फिर भी परिवहन आयुक्त ने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की अपील की। उन्होंने कहा कि ऑटो-रिक्शाओं के पीछे सूचना बोर्ड लगाना, मोबाइल एप के उपयोग को बढ़ावा देना तथा यात्रियों और चालकों के बीच विश्वास कायम करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस परियोजना की सफलता त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और कमांड कंट्रोल सेंटर की निरंतर सजगता पर निर्भर करती है। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल महिला सुरक्षा के लिए देशभर में एक आदर्श मॉडल सिद्ध होगी।

तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा में कार्यक्रम

350 स्कूली विद्यार्थियों द्वारा गुरबाणी गायन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नांदेड। हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर पवित्र तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब, नांदेड में भव्य एवं विशेष कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 350 स्कूली विद्यार्थियों द्वारा एक साथ प्रस्तुत किया गया शबद गुरबाणी का सामूहिक गायन रहा, जिसने उपस्थित संगत को भावविभोर कर दिया।

यह कार्यक्रम पवित्र तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब, नांदेड बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था। हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में 350 विद्यार्थियों ने गुरबाणी गायन के माध्यम से उन्हें यह अनूठी स्वरांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम में तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा के जत्थेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी, बोर्ड के प्रशासक डॉ. विजय सतबीर सिंह (सचिव एनबीपीएस), हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम की राज्य स्तरीय समिति के समन्वयक रामेश्वर नाइक, जसवंत सिंह बॉबी, गुरुद्वारा बोर्ड के अधीक्षक हरजीत सिंह जी कड़ेवाले सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

विद्यार्थियों के मुख से गूंजती पवित्र गुरबाणी से तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब का संपूर्ण परिसर और वातावरण भक्तिरस से ओतप्रोत हो गया। इस ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगत उपस्थित रही। उपस्थित मान्यवरों ने विद्यार्थियों के अनुशासित एवं भावपूर्ण गायन की सराहना की तथा उनका मार्गदर्शन किया।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति लगाए गए बैनरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

गवदेवी, मालाबार हिल एवं डॉ. दादासाहेब भाडकमकर मार्ग पुलिस थानों में महानगरपालिका ने मामला दर्ज कराया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन द्वारा नगर सीमा के भीतर अस्थायी विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु स्थान उपलब्ध कराए जाने के बावजूद कुछ संस्थान, संगठन एवं व्यवसायी सड़कों के दोनों ओर बिजली के खंभों पर अवैध रूप से बैनर लगा रहे हैं। ऐसे संस्थानों, संगठनों एवं व्यवसायियों के विरुद्ध लाइसेंस विभाग द्वारा गवदेवी, मालाबार हिल एवं डॉ. डी. बी. मार्ग पुलिस थानों में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई 21 एवं 22 जनवरी 2026 को दो दिनों के दौरान की गई। इस कार्रवाई में कुल 41 बैनर हटाए गए। महानगरपालिका के लाइसेंस विभाग ने अपील की है कि विज्ञापन केवल महानगरपालिका से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लगाए जाएँ। साथ ही

यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, होर्डिंग एवं पोस्टर लगाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

यह कार्रवाई बृहन्मुंबई महानगरपालिका की उपायुक्त (विशेष) श्रीमती चंदा जाधव के मार्गदर्शन में लाइसेंस विभाग द्वारा की गई। महानगरपालिका के डी सेक्शन में डॉ. गोपालराव देशमुख मार्ग (पेडर रोड), पंडिता रमाबाई मार्ग, भुलाभाई देसाई मार्ग, वॉकेश्वर, मालाबार हिल, डॉ. दादासाहेब भाडकमकर मार्ग, मौलाना शौकत अली मार्ग, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग तथा राजा राममोहन राय मार्ग पर लाइसेंस विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही गवदेवी, मालाबार हिल एवं डॉ. दादासाहेब भाडकमकर मार्ग–इन तीन पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई है। इसके अनुसार संबंधित पुलिस थानों में मामला पंजीकृत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, महानगरपालिका सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का होर्डिंग, बैनर अथवा पोस्टर प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों एवं फुटपाथों पर किसी भी विषय से संबंधित विज्ञापन होर्डिंग, बैनर अथवा पोस्टर महानगरपालिका की पूर्व अनुमति के बिना लगाना निषिद्ध है। बिना अनुमति ऐसे विज्ञापन होर्डिंग, बैनर अथवा पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध 'महाराष्ट्र संपत्ति विद्रूपण प्रतिबंध अधिनियम-1995' के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 की धाराएँ 328/328-ए एवं 471 के अंतर्गत भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लाइसेंस विभाग ने बताया कि इन प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने तथा न्यायालय में वाद दायर करने जैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं बालासाहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा श्रद्धेय बालासाहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय के एम्फीथिएटर में अतिरिक्त आयुक्त श्री सुनील पवार द्वारा प्रतिमा पूजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रशासन विभाग के उप आयुक्त श्री किसानराव पलांडे,

अतिक्रमण विभाग के उप आयुक्त डॉ. कैलाश गायकवाड़, मुख्य विधि अधिकारी श्री अभय जाधव, प्रशासनिक अधिकारी श्री दत्तात्रेय काले एवं श्री रवि जाधव सहित नवी मुंबई महानगरपालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे का ऐरोली विभाग निरीक्षण दौरा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के ऐरोली विभाग के निरीक्षण दौरे के दौरान सेक्टर 20C, ऐरोली स्थित एक भूखंड पर चल रहे भवन निर्माण कार्य में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के कई नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस पर संबंधित निर्माण कार्य को तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए। संबंधित डेवलपर जालाराम एंटरप्राइजेस को नोटिस जारी किया गया है तथा स्पष्ट किया गया है कि मानक संचालन प्रक्रिया के नियमों का पूर्ण पालन किए जाने और पुनः निरीक्षण के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। महापालिका आयुक्त ने ऐरोली थिएटर, ऐरोली-घणसोली ब्रिज, सेंट्रल लाइब्रेरी, साइंस पार्क सहित कुछ

निर्माण स्थलों तथा चल रहे सड़क सुविधा कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ कार्यों में कमियां पाई गईं। विशेष रूप से ऐरोली विभाग में पाई गई इन कमियों के संबंध में ऐरोली विभाग अधिकारी श्री नैनैश बादले, कार्यकारी अभियंता श्री संजय पाटील तथा उप अभियंता श्री बंधु शिरोसे को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उन्हें निलंबित क्यों न किया जाए।

इसी प्रकार वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से एनएमयू क्षेत्र में चल रहे निर्माण प्रकल्पों, विकास कार्यों तथा बुनियादी ढांचा कार्यों की जांच एवं निरीक्षण के लिए अतिरिक्त आयुक्त 1 एवं 2, सिटी इंजीनियर तथा शहरी नियोजन निदेशक की विशेष टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही आयुक्त स्वयं भी कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर सड़कों, स्वच्छता तथा निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे।

सम्पादकीय

दुश्मन नहीं, रास्ता बना जवानों का काल? जम्मू-कश्मीर के डोडा हादसे ने उठाए गंभीर सवाल

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हुए हादसे में जिस तरह दस जवानों की जान चली गई, वह दुर्गम इलाके में तैनात सुरक्षा बलों के सामने मौजूद बहुस्तरीय जोखिम का ही उदाहरण है। गौरतलब है कि गुरुवार को डोडा में सेना के एक बुलेटप्रूफ वाहन में सवार फौजी लगभग नौ हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित एक चौकी की ओर जा रहे थे। इस बीच खन्नी टाप के पास वाहन सड़क से फिसल कर दो सौ फुट गहरी खाई में जा गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वाहन और उसमें सवार लोगों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। दस जवानों की मौत के अलावा ग्यारह अन्य जवान बुरी तरह घायल भी हुए।

जाहिर है, आतंकवाद का सामना करने के क्रम में जानलेवा खतरों और हमलों का सामना करने के अलावा इस घटना से वहां ड्यूटी के लिए तैनात सुरक्षा बलों के सामने एक अतिरिक्त चुनौती का पता चलता है। यह इलाका अपनी बेहद मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता रहा है और वहां सुरक्षा बलों के जवानों के सामने हमेशा ही जोखिम की स्थिति बनी रहती है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच आतंकवादियों का सामना करना पहले ही एक बड़ी चुनौती रही है।

उसमें जब सुरक्षा कारणों से ही सड़कों पर सफर के क्रम में हुए हादसे में जवानों की मौत हो जाती है, तो यह वाहन चलाने में हुई मामूली चूक के खतरनाक नतीजों के साथ-साथ दुर्गम इलाकों में मौजूद रास्तों के बेहद असुरक्षित होने का भी सबूत है। सवाल है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से अतिसंवेदनशील इलाकों में सड़कों को इस हालत में कैसे छोड़ा गया है कि किसी वाहन के खाई में गिरने के बाद उसमें सवार लोगों के जिंदा बचने की गुंजाइश बेहद कम होती है।

अफसोस की बात यह है कि उस समूचे क्षेत्र में सुरक्षा बलों के सामने मौजूद अलग-अलग जोखिम के समांतर बचाव के मोर्चे पर शायद पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। वरना हादसे और जोखिम के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील जगहों पर सड़कों के किनारे मजबूत सुरक्षा घेरा या पैराफिट लगाने भर से पहाड़ी इलाकों में होने वाले हादसों में जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में वाहनों के दुर्घटना का शिकार होने और जवानों की मौत या उनके घायल होने की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। वाहन पर से चालक का नियंत्रण खोना एक कारण हो सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में संकरी और घुमावदार सड़कों के तीखे मोड़ पर फिसलन का खतरा बना रहता है।

ताजा घटना में जिस खन्नी टाप पर सेना का वाहन हादसे का शिकार हुआ, उस तरह की जगहों पर ऊंचाई और कंकड़-मिट्टी की वजह से फिसलन ज्यादा घातक हो जाती है। खासतौर पर दिसंबर-जनवरी के बीच ज्यादा ठंड और बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन आम रहती है।

ऐसे में उन सड़कों से अगर भारी सैन्य वाहन गुजरते हैं, तो ऊंचाई वाली जगहों पर कई बार वाहन पर नियंत्रण मुश्किल काम होता है और उसमें चूक की आशंका बनी रहती है। हादसों पर लगाम के लिए इलाके में तैनात जवानों को खराब मौसम और परिस्थिति के मुताबिक बेहतर प्रशिक्षण तथा वाहनों के रखरखाव के पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सड़कों के बुनियादी ढांचे पर ठोस काम हो और उसे पूरी तरह सुरक्षित बनाने के इंतजाम किए जाएं, ताकि देश की सुरक्षा और आतंकवाद का सामना करने के लिए तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के सामने हादसों में जान गंवाने की नौबत न आए।

हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड का संघर्ष, फास्ट-कामर्स- सुविधा की रफ्तार या समाज की धीमी मौत?

तेजी से फैलते उपभोक्तावादी तंत्र के बीच 'फास्ट-कामर्स' यानी तुरंत सामान हासिल करना या उसकी आपूर्ति करने का तंत्र एक ऐसी आक्रामक व्यवस्था बनकर उभरा है, जो सुविधा के नाम पर समाज की संवेदनात्मक परतों, बाजार की स्वाभाविक लय और अर्थव्यवस्था की स्थायी संरचनाओं को भीतर ही भीतर क्षीण कर रहा है। मनुष्य की आवश्यकताओं को तात्कालिकता में बांधकर यह प्रारूप न केवल हमारी जीवन-दृष्टि को उथला बना रहा है, बल्कि पूंजी के एकाधिकारवादी विस्तार को सामाजिक अनिवार्यता के रूप में आरोपित कर रहा है।

तत्काल आपूर्ति के इस कारोबार का उभार किसी साधारण तकनीकी प्रगति का संकेत भर नहीं है। यह आधुनिक पूंजीवादी संरचना की वह शाखा है, जो मानव जीवन को उत्पादन-उपभोग की निरंतर दौड़ में धकेलकर उसकी संवेदनशीलता, सामुदायिक आत्मा और उसके आर्थिक विवेक को क्रमशः नष्ट कर रहा है। सुविधा के चकाचौंध भरे आवरण के भीतर छिपी यह व्यवस्था उपभोक्ता को उस बिंदु तक ले जाती है, जहां तात्कालिक संतुष्टि को जीवन का मूल मूल्य मान लिया जाता है और किसी वस्तु की प्राप्ति में अगर कुछ क्षणों का भी विलंब हो जाए, तो व्यक्ति उसे व्यक्तिगत असुविधा नहीं, बल्कि जीवन में अस्वीकार्य बाधा समझ बैठता है।

यही वह मनोवैज्ञानिक विकृति है, जिसे पूंजीवाद अपने महत्त्वाकांक्षी विस्तार के लिए पोषित करता है। एक ऐसा उपभोक्ता, जो संयम, प्रतीक्षा, विवेक और स्थानीय संबंधों की गरिमा को भूलकर लगातार, अनवरत, आवेगपूर्ण खरीदारी के चक्र में फंसा रहे।

यह तेज-रफ्तार प्रणाली स्थानीय बाजारों के लिए एक विषैली चुनौती बन चुकी है। पुरानी किराना संरचना, छोटे व्यापारों की आत्मनिर्भर प्रणाली और पड़ोस की जीवंत आर्थिक संस्कृति इस व्यवस्थित अतिक्रमण के आगे क्षीण होती जा रही है। तीव्रगामी वाणिज्य की विशाल कंपनियां अल्गोरिद्म पर आधारित मूल्य-निर्धारण और पूंजी के असीमित संसाधनों के बल पर ऐसे दाम प्रस्तुत करती हैं, जिनसे छोटे व्यापारी प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सकते।

नतीजतन, स्थानीय अर्थव्यवस्था भयावह संकुचन की ओर बढ़ती है, आय के स्रोत केंद्रित होते जाते हैं और समाज का आर्थिक संतुलन टूटने लगता है। उपभोक्ता को सस्ती सुविधाओं का भ्रम मिलता है। मगर वास्तविकता यह है कि वह अपनी ही सामुदायिक आर्थिक सुरक्षा को घाटे के घाट उतार रहा होता है।

श्रम के क्षेत्र में भी यह प्रारूप अत्यंत अमानवीय परिस्थितियां निर्मित करता है। मिनटों में आपूर्ति की आकांक्षा सामान पहुंचाने वाले उन कर्मियों पर असाधारण दबाव डालती है, जिनके पास सुरक्षा, स्थायित्व, बीमा या सम्मानजनक श्रम-नीतियों का न्यूनतम आधार भी नहीं होता।

पूंजीवादी संरचना उनकी थकान, जोखिम, समय और जीवन को एक ऐसे अदृश्य लागत-तंत्र में बदल देती है, जिसे उपभोक्ता सुविधा के नाम पर सहज ही स्वीकार कर लेता है। यह वही जटिल पूंजीवादी विडंबना है, जहां लाभ का संचय ऊपर केंद्रित होता जाता है और श्रम का बोझ नीचे तक धकेल दिया जाता है।

तत्काल आपूर्ति का चलन मानव समाज की उन स्वाभाविक प्रक्रियाओं को नष्ट करता है, जिनके माध्यम से नस्लें, समुदाय और पड़ोस अपने भीतर सामाजिक आदान-प्रदान, संवाद और सह-अस्तित्व की संस्कृति विकसित करते थे। अब मानव संपर्क का स्थान स्क्रीन ले चुकी है, बाजारों की विविधता की जगह विभिन्न एप की एकरूपता ने ले ली है और सामुदायिक सहयोग की जगह व्यक्ति की अकेली उपभोग-यात्रा ने कब्जा कर लिया है। यह परिवर्तन सभ्यता को गति तो देता है, पर गहराई से खाली भी करता है।

कारोबार के इस स्वरूप का एक गहन दुष्प्रभाव पर्यावरणीय ह्रास के रूप में सामने आता है। तीव्र आपूर्ति की इस व्यवस्था में साजो-सामान की आपूर्ति के सूक्ष्म तंत्र का जो असंगत विस्तार हुआ है, वह सड़क-जाल, वाहन-उपयोग और ईंधन-उपभोग के रूप में एक ऐसी अदृश्य पर्यावरणीय आपदा रच रहा है, जिसकी कीमत न वर्तमान उपभोक्ता समझ रहा है और न ही पूंजी-चालित कंपनियां स्वीकार करने को तैयार हैं।

हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड को लक्ष्य बनाकर चलने वाली डिलीवरी-प्रणाली का अर्थ है अनगिनत छोटे पैकेट, असीमित प्लास्टिक, अनवरत वाहनों की आवाजाही और कार्बन-उत्सर्जन का बढ़ता दबाव। यह तरीका जलवायु-संवेदनशील देशों, विशेषकर वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है।

पूंजीवाद का स्वभाव ही यही है कि वह लागत को प्रकृति पर थोपकर लाभ को अपने केंद्र में समेट ले। तीव्र आपूर्ति इसी प्रवृत्ति का वर्तमान और अत्यधिक उग्र रूप है। उपभोक्ता को जो त्वरित सुविधा मिलती है, उसकी वास्तविक पर्यावरणीय कीमत पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों से वसूलेगी। यह सच जितना भयावह है, उतना ही अनदेखा भी। अगर समाज इस प्रणाली की पर्यावरण-विरोधी संरचना को न पहचाने, तो वह सुविधा के मोह में अपने पारिस्थितिक भविष्य को दांव पर लगा देगा।

तीव्र आपूर्ति एक ऐसा आधुनिक मिथक बन चुका है, जो सुविधा को प्रगति और तात्कालिकता को आधुनिकता का पर्याय बताता है। मगर इस चमकीली सतह के नीचे एक गहरा संरचनात्मक संकट छिपा है- संकुचित होता स्थानीय बाजार, शोषित होता श्रम, व्यवस्थित रूप से नियंत्रित होता उपभोक्ता और टूटता हुआ सामाजिक ताना-बाना।

अगर समाज इस स्वरूप को बिना विवेक स्वीकार करता रहा, तो वह धीरे-धीरे ऐसी आर्थिक निर्भरता में फंस जाएगा, जहां विकल्प, स्वतंत्रता और समुदाय- ये तीनों ही मूल्य पूंजीवादी मशीनरी के आगे अप्रासंगिक हो जाएंगे।

महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर बनकर उभरे फडणवीस

आचार्य पवन त्रिपाठी

महाराष्ट्र की महानगरपालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अभूतपूर्व जीत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हविकास की राजनीति एवं उनके राजनीतिक चातुर्य का डंका बजा दिया है और वह एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा को मिली जीत केवल सत्ता परिवर्तन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह राज्य की सामाजिक-राजनीतिक संरचना में आए एक गहरे बदलाव का संकेत भी है। 2026 के नगर निकाय चुनावों के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा अब महाराष्ट्र में केवल एक सहयोगी दल नहीं, बल्कि राजनीति की धुरी बन चुकी है।

दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति, विशेष रूप से मुंबई और ठाणे जैसे शहरी केंद्रों में 'भूमिपुत्र' और 'मराठी अस्मिता' जैसे भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित रही है। भाजपा ने इस पारंपरिक विमर्श को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सर्वसमावेशी विकास' और 'हिंदुत्व' के मिश्रण से ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस महानगरपालिका चुनावों के दौरान अपने भाषणों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाने एवं भविष्य में होनेवाले कार्यों की जानकारी देने में खर्च करते थे। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) जैसे प्रमुख शहरी निकायों में भाजपा की जीत यह दर्शाती है कि शहरी और मध्यमवर्गीय मतदाताओं ने भावनात्मक या क्षेत्रीय मुद्दों के बजाय मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बातों पर ज्यादा भरोसा किया है। अब मतदाता बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल सार्वजनिक सेवाओं, पारदर्शी प्रशासन और वैश्विक मानकों वाली नागरिक सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रमुख चुनावी नारा 'ट्रिपल इंजन सरकार' (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में एक ही दल/गठबंधन) रहा है। इस अवधारणा के पीछे तर्क यह है कि तीनों स्तरों पर सत्ता में एक ही दल होने से विकास परियोजनाओं के निष्पादन में समन्वय बढ़ेगा और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।

राज्य की अधिसंख्य महानगरपालिकाओं पर भाजपा या भाजपानीत महायुति के नियंत्रण का सीधा अर्थ होगा, राज्य के कुल बजटीय संसाधनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर नियंत्रण। महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं का संयुक्त बजट कई छोटे भारतीय राज्यों को मिलाकर उनके कुल बजट से अधिक होता है। भाजपा अब इन विशाल संसाधनों का उपयोग अपनी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास एजेंडे को सीधे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कर सकती है। इस सीधे हस्तक्षेप से न केवल परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन संभव होगा, बल्कि भाजपा का स्थानीय स्तर पर सीधा संपर्क बढ़ेगा और उसका वोट बैंक और अधिक मजबूत होगा।

हालिया चुनावी सफलताओं का श्रेय महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस की रणनीतिक कुशलता और सूक्ष्म-प्रबंधन (माइक्रो मैनेजमेंट) को जाता है। उन्होंने न केवल अपनी पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित की, बल्कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन को भी सफलतापूर्वक संभाला। इन सफलताओं ने भाजपा के भीतर देवेंद्र फडणवीस की स्थिति को निर्विवाद रूप से मजबूत किया है। उनकी रणनीतिक क्षमता और नेतृत्व कौशल ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने उनकी साख को और बढ़ाया है। यह परिणाम इस बात का भी संकेत है कि भविष्य में, भाजपा राज्य में किसी भी गठबंधन का नेतृत्व एक प्रमुख या 'बड़े भाई' की भूमिका में ही करेगी। फडणवीस का नेतृत्व भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हुआ है, और उनकी बढ़ती राजनीतिक ताकत महाराष्ट्र में पार्टी के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फडणवीस के नेतृत्व में महानगरपालिकाओं में जीत का मतलब है महाराष्ट्र की लगभग आधी आबादी तक भाजपा की सीधी पहुँच। भाजपा ने शहरी युवाओं, पेशेवर वर्गों और प्रवासियों के बीच अपनी पैठ मजबूत की है। महानगर निगमों के माध्यम से लागू किए जाने वाले प्रमुख विकास कार्य, जैसे कि मेट्रो रेल परियोजनाएं, तटीय सड़कें, स्मार्ट सिटी पहल और अन्य शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, भाजपा को एक 'विकास-समर्थक' और आधुनिक पार्टी के रूप में स्थापित करती हैं। इस शहरी केंद्रित विकास के नैरेटिव का लाभ भाजपा को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी मिल सकता है, क्योंकि शहरी विकास अक्सर आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है।

भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान पिछली सरकारों और नगर निकायों में व्याप्त कथित 'कमीशन राज' और भ्रष्टाचार को एक प्रमुख मुद्दा बनाया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मतदाताओं को यह आश्वासन दिया कि भाजपा के नेतृत्व में एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान किया जाएगा। अब ज्यादातर नगर निकायों में सत्ता प्राप्त करने के बाद भाजपा पर यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी है कि वह वास्तव में पारदर्शिता और जवाबदेही ला सकती है। यदि भाजपा शहरी शासन में महत्वपूर्ण सुधार लाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सफल रहती है, तो यह उसके लिए 2029 के विधानसभा चुनावों का 'प्रवेश द्वार' साबित हो सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं महाराष्ट्र में अपने युवा नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा ने अपने सामाजिक आधार का सफलतापूर्वक विस्तार किया है। पार्टी ने अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और मराठा समुदायों में भी अपनी पैठ मजबूत की है, जो महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण मतदाता समूह हैं। नगर निगम चुनावों में, भाजपा ने विभिन्न जातियों और समुदायों के उम्मीदवारों को टिकट वितरण में प्रतिनिधित्व दिया। इस 'सोशल इंजीनियरिंग' रणनीति से स्थानीय स्तर पर नए नेतृत्व का उदय हो रहा है, जो अपने समुदायों में पार्टी के लिए समर्थन जुटा सकते हैं। यह विस्तार भाजपा को भविष्य में अन्य दलों के पारंपरिक जातीय वोट बैंकों में सेंध लगाने में मदद करेगा। वास्तव में महाराष्ट्र की महानगरपालिकाओं में भाजपा का वर्तमान प्रभुत्व केवल एक चुनावी जीत से कहीं अधिक है। इसने राज्य की राजनीति में एक मौलिक राजनीतिक पुनर्गठन का रास्ता खोल दिया है। इसने महाराष्ट्र की राजनीति के पारंपरिक 'पावर सेंटर्स' को चुनौती दी है और एक नई राजनीतिक गतिशीलता स्थापित की है। भविष्य में इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि राज्य की राजनीति 'गठबंधन की मजबूरी' और खंडित जनादेश के युग से निकलकर 'एकदलीय प्रभुत्व' या एक प्रमुख गठबंधन के वर्चस्व की ओर बढ़ सकती है।

पढ़ाने से ज्यादा सरकारी कामों में उलझा दिए गए हैं शिक्षक क्या अब सबसे सस्ता सरकारी संसाधन बन गए हैं अध्यापक?

एक समय था जब शिक्षक समाज का पथप्रदर्शक माना जाता था। आज वही शिक्षक व्यवस्था की हर कमी को पूरा करने वाला सबसे सुविधाजनक संसाधन बनता जा रहा है। सुरक्षा, निगरानी और प्रशासनिक आवश्यकताओं के नाम पर उसे ऐसे कार्य भी करने पड़ रहे हैं, जिनका असल में शिक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में जिस बदलाव की अपेक्षा थी, कई बार उसके विपरीत भी हो रहा है। निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

कुछ समय पहले शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों को आवारा कुत्तों से सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने की खबर आई। इस क्रम में सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों की निगरानी तथा उनसे बचाव के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपने की भी खबर थी। औपचारिक रूप से यह व्यवस्था सुरक्षा के उद्देश्य से है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह आदेश एक गहरे और असहज प्रश्न को जन्म देता है। क्या शिक्षकों को इस तरह के या अन्य गैर-शिक्षण कार्यों में लगाना शैक्षणिक दायित्वों के अनुरूप है?

शिक्षण कार्य को बेहद जिम्मेदारी का और गरिमापूर्ण कार्य माना जाता है। मगर क्या गैर-शिक्षण कार्य से संबंधित दिशा-निर्देश शिक्षकों की गरिमा के साथ न्याय करते हैं? यह प्रश्न इसलिए और गंभीर हो जाता है, क्योंकि यह कोई पहला अवसर नहीं है। इससे पहले भी शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी, जनगणना, पशुगणना, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, सत्यापन, सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता अभियान, कोविड निगरानी, सामाजिक अभियानों और अन्य अनेक गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगातार लगाया जाता रहा है।

इन परिस्थितियों में यह बहस स्वाभाविक है कि क्या शिक्षक को अब हर प्रशासनिक दायित्व को पूरा करने वाला सुलभ मानव संसाधन मान लिया गया है? सुरक्षा और संवेदनशीलता जैसे मुद्दों की आड़ में अगर शिक्षक को उसके मूल कार्य, यानी पढ़ाने, शोध करने, अकादमिक मार्गदर्शन इत्यादि से निरंतर दूर किया जाएगा, तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव केवल शिक्षकों पर नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था और समाज के बौद्धिक भविष्य पर पड़ेगा। यह सवाल अब केवल आदेश की वैधानिकता का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और प्राथमिकता का भी है। किसी भी राष्ट्र में शिक्षक की गरिमा का क्षरण उस समाज की आत्मबोधहीनता का संकेत होता है। शिक्षक की उपेक्षा किसी एक वर्ग का अपमान नहीं, बल्कि वह उस विचार की उपेक्षा होती है कि ज्ञान, विवेक और प्रश्न पूछने की क्षमता किसी समाज के लिए कितनी आवश्यक है। अगर हम शिक्षक से निरंतर ऐसे कार्य करा रहे हैं जो उसकी पेशागत पहचान को धुंधला करते हैं, तो यह आत्मचिंतन आवश्यक है कि क्या हम अनजाने में शिक्षा को नहीं, बल्कि शिक्षक को ही अप्रासंगिक बना रहे हैं! आज जिस सहजता के साथ शिक्षकों को आवारा पशुओं की गिनती, निगरानी और नियंत्रण जैसे कार्यों में लगाने की खबरों को लिया जा रहा है, वह किसी साधारण प्रशासनिक निर्णय का परिणाम नहीं है। यह उस मानसिकता का उद्घाटन है, जिसमें शिक्षक की भूमिका को क्रमशः गौण और सुविधाजनक उपयोगितावादी बना दिया गया है। जिन कार्यों के लिए नगर निगम, नगरपालिका परिषद और ग्राम पंचायतों में पृथक कर्मचारी, विभाग और बजट निर्धारित हैं, उन्हीं कार्यों के लिए शिक्षकों को खड़ा कर देना यह संकेत देता है कि व्यवस्था की दृष्टि में शिक्षक का समय, श्रम और बौद्धिक क्षमता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, बल्कि शिक्षक अब सबसे सस्ता विकल्प बन चुके हैं।

जिस शिक्षक से समाज विवेकशील नागरिक तैयार करने की अपेक्षा करता है, उसी को आज यह अप्रत्यक्ष संदेश दिया जा रहा है कि उसका मूल दायित्व पढ़ाना, शोध करना, विचार और प्रश्न गढ़ना अब प्राथमिकता की सूची में नहीं है। कक्षा में विद्यार्थी हैं या नहीं, शिक्षण की गुणवत्ता लगातार क्यों कम होती जा रही है? शोध हो रहा है या नहीं, इससे अधिक महत्त्वपूर्ण यह माना जा रहा है कि जहां प्रशासनिक तंत्र अपने किसी कार्य को करने में असफल हो जाए, वहां उसकी भरपाई के लिए शिक्षक को आसानी से लगा दिया जाए।

यह स्थिति केवल पेशागत गरिमा का हनन नहीं, बल्कि शिक्षा को एक कमतर महत्त्व की गतिविधि मान लेने की प्रवृत्ति को उजागर करती है। विडंबना यह है कि जिस समाज में शिक्षक को कभी गुरु, आचार्य और राष्ट्र निर्माता कहा गया, उसी समाज में उसे ऐसा बहुउद्देशीय सरकारी श्रमिक समझ लिया गया है, जिससे बिना किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण और उचित पारितोषिक के कोई भी काम करवाया जा सकता है। चुनावी ड्यूटी हो, सर्वेक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण या सत्यापन हो, हर जगह शिक्षकों को आगे कर दिया जाता है।

यह धारणा धीरे-धीरे स्थापित की जा रही है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलताओं को ढोने वाला एक आज्ञाकारी माध्यम है। इस दृष्टिकोण में शिक्षक की पहचान बौद्धिक पूंजी के रूप में नहीं, बल्कि संकट-प्रबंधन के सुलभ संसाधन के रूप में होती जा रही है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि इस निरंतर अपमान के बीच शिक्षक समुदाय की चुप्पी स्वयं एक सवाल बन चुकी है।

यह चुप्पी केवल विवशता की नहीं, बल्कि उपेक्षा के साथ समझौता कर लेने की आदत का संकेत भी है। जब शिक्षक अपने सम्मान के सवाल पर मौन साध लेता है, तब समाज और व्यवस्था दोनों यह मान लेते हैं कि यह स्थिति न केवल स्वीकार्य है, बल्कि स्थायी भी है। यहीं से शिक्षा के क्षरण की प्रक्रिया शुरू होने लगती है।

यदि हम विकसित देशों की ओर दृष्टि डालें, तो हमें एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। फिनलैंड में शिक्षक बनना केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और बौद्धिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। वहां शिक्षक को गैर-शैक्षणिक सरकारी कार्यों में लगाना लगभग असंभव माना जाता है, क्योंकि वहां पर राज्य यह समझता है कि शिक्षक का समय सीधे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा है। इसी प्रकार जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में शिक्षक न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यंत सम्मानित हैं। वहां शिक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह व्यवस्था की कमियों की भरपाई करे, बल्कि यह अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों की क्षमता, अनुशासन और नवाचार को आकार दे।

इन देशों की प्रगति किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि उस स्पष्ट समझ का परिणाम है जो यह मानती है कि शिक्षक को यदि कक्षा से हटाया गया, तो राष्ट्र दिशा से भटक जाएगा। वहां शिक्षकों से पशुओं की गणना और निगरानी नहीं करवाई जाती, बल्कि संभावनाओं की गिनती करवाई जाती है।

वहीं यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षक का अपमान दीर्घकाल में राष्ट्र के लिए एक खतरे का संकेत है। अंततः यह सवाल किसी एक आदेश, किसी फाइल या किसी विभाग तक सीमित नहीं है, यह उस बौद्धिक आत्मा का प्रश्न है जिसे हम राष्ट्र के रूप में गढ़ रहे हैं। जब शिक्षक से उसका मूल धर्म छीन कर उसे व्यवस्था की असफलताओं का मूक वाहक बना दिया जाता है, तब शिक्षा उपेक्षित ही नहीं होती, बल्कि अज्ञान को संस्थागत वैधता मिल जाती है। क्या कोई समाज सचमुच प्रगति की आकांक्षा कर सकता है, जहां शिक्षक कक्षा में नहीं, बल्कि सड़कों पर अन्य कार्य करता हुआ अधिक उपयोगी समझा जाए?

जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन चार परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण सहित समय सीमा में पूर्ण करने के दिये निर्देश

कार्य में तीव्रता लाते हुए इसे शीघ्र पूर्ण कर क्रियाशील करने का डीएम ने दिया निर्देश

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने शुक्रवार को जनपद भदोही में संचालित चार महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं समय-सीमा का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को सभी परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन 100 बेडेड अन्तः रोगी कक्ष (आईपीडी) भवन एवं 50 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं जनपद के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य में और तेजी लाते हुए इसे शीघ्र पूर्ण कर क्रियाशील करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़ी इस परियोजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि निर्माणाधीन आईपीडी भवन में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त वार्ड, डॉक्टर कक्ष, ऑपरेशन थियेटर, प्रयोगशाला सहित अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। भवन के पूर्ण होने के पश्चात जनपदवासियों को बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी, साथ ही अस्पताल पर बढ़ते मरीजों के दबाव में भी कमी आएगी। उन्होंने अधिकारियों को कार्य की सतत निगरानी सुनिश्चित करने तथा गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

इसके पश्चात जिलाधिकारी ने पुलिस लाइन के बगल स्थित श्री काशीराज संस्कृत महाविद्यालय में निर्माणाधीन शैक्षिक भवन एवं छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां भी कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपस्थित जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) अंशुमान द्वारा महाविद्यालय की अतीत एवं वर्तमान शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि काशी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान के अंतर्गत जनपद भदोही में संस्कृत की परम्परा एवं मूल्यों को अक्षुण्य बनाए रखने में यह महाविद्यालय एवं इसका नवीन भवन महत्वपूर्ण एवं नैतिक भूमिका निभाएगा।

अंत में जिलाधिकारी ने पिपरीस स्थित निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक, छात्रावास सहित अन्य निर्माणाधीन भवनों का अवलोकन किया। कॉलेज परिसर में आवागमन के रास्ते एवं बाउंड्रीवाल से संबंधित ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सर्वप्रथम ग्रामीणों के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसी को असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के संचालन से शीघ्र ही जनपद भदोही सहित आसपास के जनपदों के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त सभी चारों निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं प्रगति समीक्षा करने के आदेश दिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी बाल गोबिन्द शुक्ल, प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पीडब्लूडी एई सुभाष चंद्र, डीईएसटीओ शशिकांत, जिला सूचना अधिकारी डॉ0 पंकज कुमार, राजकीय निर्माण निगम के अभियंता, सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आईजीआरएस की बैठक कलेक्टेट्ट सभागार में सम्पन्न

शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, गलत स्पेशल क्लोज़ पर होगी कार्यवाही-अपर जिलाधिकारी

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी के कुशल निर्देशन में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व कुंवर वीरेन्द्र मौर्य एवं अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह की अध्यक्षता में आईजीआरएस मुख्यमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी संदर्भ, तहसील दिवस संदर्भ सहित अन्य संदर्भों के सापेक्ष निस्तारित एवं लम्बित शिकायतों/प्रकरणों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुयी। बी श्रेणी की समीक्षा के दौरान तहसीलदार औराई, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही सी श्रेणी के संदर्भ प्रकरण अधिक होने पर कड़ी फटकार लगाई साथ ही आइजीआरएस हेल्पलाइन सबसे ज्यादा असंतुष्ट की फीडबैक सहायक श्रम आयुक्त सब रजिस्टार औराई बाल विकास परियोजना अधिकारी डीघ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डीघ को कड़ा निर्देश दिया कि शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर प्रकरण को निक्षेपित करें, साथ ही तहसील न्यायालय में बेचाराधिन मुकदमों को प्राथमिकता से निस्तारण कराने के साथ-साथ सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन विभागों मे अवमानना के प्रकरण हैं शीघ्र निस्तारण कराए अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी जवाब दे ही तय की जाएगी। जनसंवाद दिवस पर शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर उनकी समस्याओं का निस्तारण गुणवत्ता पूर्वक कराए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही पूरे मनोयोग से कार्य करें, जिससे जनपद की रैंक अच्छी बनी रहे। निर्देश दिया कि शिकायतों को अधिकारी कटेगरी वाईज कर सही ढंग व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकांश शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर शिकायतकर्ता को वार्ता कर संतुष्ट करने के उपरान्त ही आख्या अपलोड की जाए। केवल वे ही शिकायत स्पेशल क्लोज़ की जाए, जो पोर्टल पर उपलब्ध स्पेशल क्लोज़ की श्रेणी में आती हो। गलत फ्लैग लगाकर स्पेशल क्लोज़ करने पर कार्यवाही की जाएगी। प्रायः यह देखा जा रहा है कि जनपद स्तर से एक ही शिकायत को कई बार फीड किया जा रहा है एवं एक ही मोबाईल नंबर से अलग अलग शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। विश्लेषण में यह भी पाया गया है की मोबाईल नंबर शिकायतकर्ता का न होकर किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति का है। जिस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत है उसी से जांच कदापि न कराई जाए। यह भी समीक्षा कर लें की उनके यहाँ किस क्षेत्र या किस विभाग शिकायत श्रेणी मे सर्वाधिक शिकायतें आ रही हैं और उसका निराकरण कराएं।

उदाहरणार्थ कतिपय जनपदों में प्रमाणपत्र बनाने के संबंध में अधिक शिकायत दर्ज हो रही हैं। पूर्व में दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद स्तर से निस्तारण की गुणवत्ता का क्रॉस वेरीफिकेशन करने के उपरान्त ही आख्या अपलोड या स्पेशल क्लोज की कार्यवाही की जाए।

अपर जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निरस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी फरियादियों/शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के प्रति बेहद गम्भीर है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करके रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के डिफाल्टर होने व निस्तारित शिकायतों की खराब गुणवत्ता पाये जाने पर कुछ विभागीय अधिकारियों को इसमें सुधार लाने की कड़ी चेतावनी दिया, कहा कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिये कि निस्तारण की गुणवत्ता खराब होने के कारण उच्च स्तर से शिकायतें पुनः वापस आ जाये। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता का पक्ष भी अवश्य सुना जाए और सदंर्भो के निस्तारण के परिणाम से भी शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाए। क्योंकि शिकायतकर्ता की संतृष्टि ही संदर्भो का निस्तारण का मूल लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आईजीआरएस का पैरामीटर बदल गया है असंतुष्ट फीडबैक वाले प्रकरणों को सही ढंग से निस्तारण कराए।

भदोही पुलिस ने वापस कराए साइबर ठगी के रुपये

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जनपद की साइबर हेल्प डेस्क ने एक बार फिर त्वरित कार्यवाही करते हुए ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति की गाढ़ी कमाई वापस कराई है। थाना ज्ञानपुर निवासी रंजीत कुमार मिश्रा के खाते से अज्ञात तरीके से 21, 500 रुपये पार हो गए थे। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने के साइबर डेस्क पर की थी। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में साइबर टीम ने तत्काल संबंधित बैंक और पेमेंट गेटवे से समन्वय स्थापित किया। टीम की तत्परता से ठगी गई पूरी धनराशि रंजीत के खाते में सफलतापूर्वक वापस आ गई। अपना पैसा वापस पाकर पीड़ित ने भदोही पुलिस और साइबर टीम का आभार व्यक्त किया। एसपी ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते कार्यवाही की जा सके।

आरोग्य भारती गोरक्ष प्रांत की बैठक सम्पन्न

गोरखपुर। 21 जनवरी, 2026 को आरोग्य भारती गोरक्ष प्रांत की एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें संगठन में अधिकाधिक सदस्यों को जोड़ने एवं इसके प्रकल्पों को प्रभावी तरीक़े से जन सामान्य तक पहुँचाने पर विस्तृत चर्चा हुई । कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरक्ष प्रांत के अध्यक्ष डॉ डी पी सिंह ने की । इस अवसर पर आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ जी एस तोमर ने अपने उद्बोधन में पंच परिवर्तन (सामाजिक समरसता, कुटुम्ब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी भाव तथा नागरिक कर्तव्य) को विकसित भारत की आधारशिला बताया । उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें भारतीय ज्ञान परम्परा को पुनः जन जन तक पहुँचाना है । नवोन्मेष के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारी समृद्ध संस्कृति विश्व के

आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है । इसे और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हमें इसके पीछे छिपी वैज्ञानिकता को वैश्विक मानवता के समक्ष उनकी अपनी भाषा में रखना होगा । अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉ डी पी सिंह ने संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एकजुटता के महत्व पर प्रकाश डाला । डॉ शशिकांत सिंह ने आगामी 20-21 फ़रवरी को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में होने जा रहे अन्तरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आरोग्य भारती के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया । इस अवसर पर डॉ प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी, डॉ अंजनी कुमार सिंह, डॉ जयन्त नाथ, डॉ लालमणि चौरसिया, डॉ कमलेश पाण्डेय, डॉ विनम्र शर्मा, डॉ डी के सिंह, डॉ रमाकांत द्विवेदी, डॉ लक्ष्मी अग्निहोत्री सहित लगभग तेतीस सदस्यों ने प्रतिभाग किया । कार्यक्रम का प्रारंभ धन्वंतरि स्तवन से हुआ एवं समापन शांति मंत्र के साथ सम्पन्न हुआ ।

सौ सैया अस्पताल व संस्कृत महाविद्यालय का डीएम ने किया निरीक्षण

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जनपद में स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में जिलाधिकारी शैलेष कुमार शुक्रवार को सौ सैया संयुक्त चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में बन रहे आईपीडी वार्ड एवं 50 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की और संबंधित कार्यदायी संस्था व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, मानकों का पालन और समयबद्ध पूर्णता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए तथा

कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूर्ण कर जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने पुलिस लाइन के समीप स्थित श्री काशीराज राजकीय संस्कृत महाविद्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं भौतिक सुविधाओं की समीक्षा की। कक्षाओं, भवनों, मूलभूत सुविधाओं एवं परिसर की स्थिति का जायजा लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार एवं व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही किसी भी समाज के विकास की आधारशिला हैं और शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में इन दोनों क्षेत्रों में निरंतर सुधार किया जा रहा है। निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ आमजन तक शीघ्र और प्रभावी रूप से पहुंचे। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

गणतंत्र दिवस परेड के लिए एसपी ने जाँचा रिहर्सल

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। आगामी 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन ज्ञानपुर में आयोजित होने वाली भव्य परेड की तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड पहुंचकर चल रहे रिहर्सल का बारीकी से निरीक्षण किया।

गणतंत्र दिवस की परेड में एकरूपता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जनपदीय पुलिस की विभिन्न टुकड़ियाँ पिछले एक महीने से कड़ा अभ्यास कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने परेड की भव्यता और जवानों के प्रदर्शन को सराहा। उन्होंने परेड में शामिल प्रतिभागियों और कार्यक्रम आयोजकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व के इस गौरवशाली आयोजन को अत्यधिक सुसज्जित और त्रुटिहीन बनाया जाए।

रिहर्सल के दौरान पुलिस जवानों द्वारा किए गए शानदार मार्च पास्ट और प्रदर्शन ने आगामी समारोह की भव्यता की झलक पेश की। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

संदीप के अर्धशतक से सेवाश्रम इंटर कॉलेज ने मुरादाबाद को हराया

शशांक इलेवन ने जौनपुर को हराकर किया प्रतियोगिता से बाहर

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। सुरियावां क्षेत्र स्थित महर्षि आज़ाद स्टेडियम, मेढ़ी में तेजधर ब्रह्मबाबा खेल समिति के तत्वावधान में आयोजित महर्षि आज़ाद राज्यस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के छठवें दिन शुक्रवार को दो रोमांचक मुकाबले खेले गए। दोनों मैचों में दर्शकों को उच्चस्तरीय और संघर्षपूर्ण क्रिकेट देखने को मिला।

दिन का पहला मुकाबला मुरादाबाद और सेवाश्रम इंटर कॉलेज, सुरियावां के बीच खेला गया, जबकि दूसरा मैच शशांक इलेवन मोढ़ एवं जौनपुर की टीमों के बीच हुआ।

पहले मुकाबले में सेवाश्रम इंटर कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुरादाबाद को तीन विकेट से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सेवाश्रम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए मुरादाबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 171 रन बनाए। मुरादाबाद की ओर से पर्व चौहान ने 37 गेंदों पर 57 रन तथा तरुण पोसवाल ने 49 गेंदों पर 53 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। गेंदबाजी में सेवाश्रम के पवन कुमार ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि सोनू शर्मा को एक सफलता मिली।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेवाश्रम इंटर कॉलेज की शुरुआत भले ही धीमी रही, लेकिन संदीप भारतिया ने आक्रामक अंदाज में

बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर 53 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर मैच का रुख बदल दिया। अंतिम ओवरों में अवनीश मिश्रा (नाबाद 23 रन) एवं सनी पांडे (नाबाद 14 रन) ने संयम और सूझबूझ के साथ खेलते हुए टीम को 19.2 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन तक पहुंचाकर जीत दिला दी। दिन के दूसरे मुकाबले में शशांक इलेवन ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए जौनपुर की टीम को 87 रनों से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए शशांक इलेवन ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 166 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में जौनपुर की टीम शशांक इलेवन के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 12.4 ओवर में मात्र 79 रन पर ऑलआउट हो गई। इससे पूर्व छात्रनेता अशोक सैनी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने बताया कि शनिवार को पहला मुकाबला मऊ नाथ भंजन बनाम बांदा, जबकि दूसरा मुकाबला गाजियाबाद बनाम लखनऊ के बीच खेला जाएगा।

इस अवसर पर समिति अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सचिव अमर बहादुर सिंह, विजयशंकर राय, राजमणि पांडेय, मथुरा प्रसाद यादव, राजकुमार सरोज, जेपी सिंह, सन्तोष पांडेय शास्त्री, श्याम बहादुर यादव, परमेंद्र गौतम, मनोज गौतम, अतुल सिंह, नितेश श्रीवास्तव, सनी सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

आरक्षण की घोषणा होते ही भिवंडी मनपा मेयर पद को लेकर रस्साकसी शुरू

बहुमत के अभाव में हॉर्स ट्रेडिंग की अटकलें तेज, सियासी जोड़-तोड़ चरम पर

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका में महापौर पद को लेकर सियासी सरगर्मी अचानक तेज हो गई है। जैसे ही महापौर पद को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किया गया, वैसे ही सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने स्तर पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 90 सदस्यीय मनपा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण राजनीतिक जोड़-तोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चाएं जोरों पर हैं।

वर्तमान समीकरणों पर नजर डालें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसके 30 नगरसेवक चुनकर आए हैं। यदि इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के 12 नगरसेवकों का साथ जुड़ता है तो यह आंकड़ा 42 तक पहुंच जाता है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 46 से महज चार कम है। ऐसे में कोणार्क विकास आघाड़ी के प्रमुख और पूर्व महापौर विलास पाटिल के पास मौजूद 4 नगरसेवक निर्णायक साबित हो सकते

हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह गठजोड़ बनता है तो कांग्रेस-राकांपा-सपा खेमे का महापौर बनना लगभग तय माना जा रहा है। विलास पाटिल का राजनीतिक अनुभव और नगरसेवकों को साथ जोड़ने की उनकी क्षमता किसी से छिपी नहीं है। अतीत में वे कम संख्या बल के बावजूद बहुमत जुटाकर महापौर बनाने का 'करिश्मा' कर चुके हैं। कांग्रेस खेमे में तारिक अंसारी, प्रशांत लाड, विलास पाटिल और प्रतिभा पाटिल जैसे नाम संभावित दावेदारों के तौर पर सामने आ रहे हैं।

दूसरी ओर, भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) की महायुति के पास कुल मिलाकर करीब 32 नगरसेवक हैं, जो बहुमत से काफी पीछे हैं। उन्हें महापौर बनाने के लिए कम से कम 14 अतिरिक्त नगरसेवकों के समर्थन की जरूरत होगी। यदि राकांपा (शरद) के 12 और पूर्व महापौर जावेद दलवी के 3 नगरसेवकों का साथ मिलता है, तो भाजपा भी अपना महापौर बना सकती है। भाजपा की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के भतीजे सुमित पाटिल, साफ-सुथरी छवि वाले नारायण चौधरी और संतोष शेट्टी को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अंदरखाने जोरदार रणनीति पर काम कर रही है और राजनीतिक चमत्कार करने का उसका पुराना रिकॉर्ड भी चर्चा में है।

इस पूरे समीकरण में सपा विधायक रईस शेख की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सपा के नगरसेवकों और विधायक रईस शेख का रुख जिस ओर होगा, उसी ओर भिवंडी का महापौर तय हो सकता है। इतिहास भी गवाह है कि कोणार्क विकास आघाड़ी इससे पहले कम संख्या में नगरसेवक होने के बावजूद महापौर पद हासिल कर चुकी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद पार्टी के 18 नगरसेवकों की बगावत से कोणार्क ने महापौर पद पर कब्जा किया था। उसी तर्ज पर इस बार भी सियासी उलटफेर से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है और भिवंडी महानगरपालिका की महापौर की कुर्सी आखिर किसके हिस्से आती है।

नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा

भिवंडी। भिवंडी शहर के पुलिस स्टेशन में नाबालिग लड़कियों को प्रताड़ित करने के मामले में पोस्को के तहत दर्ज मामले की सुनवाई भिवंडी सत्र न्यायालय में हुई और इस मामले के आरोपी को न्यायाधीश ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार भिवंडी के कामतघर इलाके के भाग्यनगर निवासी 30 वर्षीय

आरोपी पवन कुमार दिनेशचंद केसरवानी भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दो पांच वर्षीय नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस संबंध में, 2020 में भिवंडी स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एन.के. करांडे की अदालत में, सरकारी वकील एड सी.बी. नवले और एड वी.एम. मुंडे ने सरकारी पक्ष प्रस्तुत किया, जबकि भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कृष्णदेव खराडे के मार्गदर्शन में, जांच अधिकारी सेवानिवृत्त पुलिस सब-इंस्पेक्टर अनिल पाटिल, अदालत में पैरवी करने वाले पुलिस कांस्टेबल अभिमन्यु पाटोले, महिला पुलिस कांस्टेबल ए.एस. सगाथिया, समन और वारंट तामील करने वाले पुलिस कांस्टेबल मडवी और रामराजे ने अपराध से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने आरोपी पवन कुमार दिनेशचंद केसरवानी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और यदि वह 5,000 रुपये का जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।

भिवंडी में विवाहिता पर घरवालों का कहर ..

पति, सास-ससुर, ननद और देवर पर जानलेवा हमले व उत्पीड़न का आरोप

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी में घरेलू हिंसा के मामलों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोनगांव और निजामपुरा पुलिस थाना क्षेत्र से सामने आए दो अलग-अलग मामलों में विवाहिता महिलाओं ने अपने ही ससुराल वालों पर बेरहमी से मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहला मामला कोनगांव पुलिस थाना क्षेत्र का है। पीड़िता (35) ने शिकायत में बताया कि वह अपने पति विजय मोर्चा, सास-ससुर, ननद और देवर के साथ पृथ्वीराज अपार्टमेंट, वाटर सप्लाई रोड, मंगल बाजार इलाके में रहती थी। 14 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे घरेलू विवाद को लेकर पहले गाली-गलौज हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। पिड़िता का आरोप है कि पति विजय, ननद सविता, जेठानी निशा और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर उस पर हमला किया। उसे लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडे से पीटा गया, जिससे सिर, पीठ और हाथों में गंभीर चोटें आईं। मारपीट में उसके हाथ की एक उंगली फ्रैक्चर हो गई। घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसी तरह का एक और चौंकाने वाला मामला निजामपुरा पुलिस थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां एक विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुराल वाले उस पर पैसों की मांग को लेकर दबाव बनाते थे। पीड़िता का कहना है कि ससुराल वालों ने उस पर तंत्र-मंत्र और काले जादू का आरोप लगाकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं, इलाज कराने से भी रोका गया और अंततः बच्चों के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों मामलों में मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और गवाहों के आधार पर जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है और दोष सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन घटनाओं ने एक बार फिर भिवंडी में घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं को उजागर किया है। सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित महिलाओं को न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस बना सियासी अखाड़ा

भिवंडी में उत्तर भारतीय समाज दो भागों में बंटा

एक ही दिन- एक ही समय समाज का अलग अलग कार्यक्रम

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, जो कभी उत्तर भारतीय समाज की एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता था, अब भिवंडी में खुलेआम सियासी टकराव और वर्चस्व की लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है। स्थापना दिवस के दूसरे ही दिन शहर में एक ही समय पर दो अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए हैं, जिससे उत्तर भारतीय समाज का गहरा बंटवारा सामने आ गया है।

हैरानी की बात यह है कि दोनों गुटों के आयोजनों में मुख्य अतिथि के रूप में मराठी नेताओं को बुलाया गया है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश की अस्मिता का उत्सव है या स्थानीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने का जरिया। सूत्रों के अनुसार, कार्यक्रमों से पहले ही चंदा वसूली का खेल पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। दुकानदारों, व्यापारियों और समाज के लोगों पर खुले और परोक्ष दबाव बनाए जाने की चर्चा है। कई लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि स्थापना दिवस अब 'सम्मान का पर्व' नहीं, बल्कि 'पावती और पोस्टर का उत्सव' बनता जा रहा है।

उत्तर भारतीय समाज सेवा संस्था की आंतरिक बनावट भी सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक संस्था में 7 ठाकुर, 5 ब्राह्मण, एक आहिर और एक बनिया शामिल हैं। इस आंकड़े ने समाज के भीतर यह बहस छेड़ दी है कि क्या यह संस्था पूरे उत्तर भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है या कुछ चुनिंदा जातियों का क्लब बनकर रह गई है।

इस पूरे विवाद पर भाजपा उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के भिवंडी शहर अध्यक्ष मंगेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'हम चंदा-पावती वाले नेता नहीं हैं। समाज को लूटकर राजनीति करने वालों से हमारा कोई लेना-देना नहीं।' उनके इस बयान ने भिवंडी की सियासत में हलचल और तेज कर दी है।

गौरतलब है कि भिवंडी में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को बड़े स्तर पर मनाने की परंपरा एमपी चुनाव के दौर में शुरू हुई थी। तब इसे समाज को संगठित करने की पहल बताया गया था, लेकिन अब वही आयोजन गुटबाजी, होड़ और शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन चुका है। हर कोई खुद को समाज का ठेकेदार साबित करने की दौड़ में शामिल नजर आ रहा है।

वरिष्ठ समाजसेवियों का कहना है कि यदि समय रहते इस खतरनाक बंटवारे पर लगाम नहीं लगी, तो उत्तर भारतीय समाज की सामाजिक एकता को गहरा नुकसान हो सकता है। स्थापना दिवस, जो जोड़ने के लिए था, वही अब तोड़ने का हथियार बनता दिख रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर भारतीय समाज इस सियासी खेल को समझ पाएगा या फिर हर साल स्थापना दिवस इसी तरह गुटों की ताकत आजमाने का मंच बनकर रह जाएगा।

ट्रक से जिंक इंगॉट्स की सनसनीखेज चोरी

1.05 लाख रुपये का माल गायब, संगठित गिरोह की आशंका

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी के वलगांव इलाके में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। यहां अरिहंत कंपाउंड में खड़े एक ट्रक से अज्ञात चोरों ने जिंक इंगॉट्स की खेप चोरी कर ली। चोरी गए माल की कीमत करीब 1 लाख 5 हजार रुपये बताई जा रही है। इस घटना के बाद औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। नारपोली पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता मनोज कल्याण सिंह (53) पेशे से सुपरवाइजर हैं और वलगांव, दापोड़ा रोड स्थित अरिहंत कंपाउंड गोदाम नंबर 11 में काम करते हैं। 20 जनवरी की रात करीब 10 बजे जिंक इंगॉट्स से भरा एक ट्रक कंपाउंड में पार्क किया गया था। अगली सुबह 21 जनवरी को करीब 7 बजे जब ट्रक की जांच की गई, तो उसमें से जिंक इंगॉट्स की 11 प्लेटें गायब पाई गईं। चोरी गए जिंक इंगॉट्स का कुल वजन करीब 12 टन बताया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1,05,152 आंकी गई है। हैरानी की बात यह है कि ट्रक में किसी तरह की तोड़फोड़ या जबरन घुसपैठ के निशान नहीं मिले हैं। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि चोरी पूरी योजना के तहत और संभवतः अंदरूनी जानकारी के आधार पर की गई। मनोज सिंह की शिकायत पर नारपोली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से भी गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चोरी किस समय और कैसे हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला संगठित धातु चोरी गिरोह से जुड़ा हो सकता है, जो औद्योगिक इलाकों में खड़े ट्रकों को निशाना बनाता है। भिवंडी जैसे बड़े वेयरहाउस और ट्रांसपोर्ट हब में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इस घटना के बाद ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने प्रशासन से औद्योगिक क्षेत्रों में रात की गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है।

100 बोतल कफ सिरप जब्त

मौत का सिरप बेंच रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी शहर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ शांतिनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित खांसी की सिरप की तस्करी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बिलाल नगर इलाके से एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 18,300 रुपये कीमत की नशीली दवाइयों की खेप जब्त की है। इस कार्रवाई से इलाके में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता हेड कांस्टेबल किरण हनुमंत जाधव को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक नशीली खांसी की सिरप बेचने के उद्देश्य से बिलाल नगर इलाके में घूम रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए शांतिनगर पुलिस ने तत्काल जाल बिछाया और 22 जनवरी की सुबह करीब 9:30 बजे बिलाल नगर, भंगारवाला के सामने छापेमारी की।इस दौरान पुलिस ने जिशान अख्तर शेख (26) नामक युवक को संदिग्ध हालत में रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद एक सफेद प्लास्टिक की बोरी से प्रतिबंधित खांसी की सिरप की 100 बोतलें बरामद की गईं। जांच में पाया गया कि जब्त की गई सिरप में Triprolidine Hydrochloride और Codeine Phosphate जैसे नशीले तत्व मौजूद थे, जिनकी बिक्री बिना डॉक्टर के पर्चे के करना कानूनन अपराध है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास दवा बेचने से संबंधित कोई लाइसेंस, बिल या वैध परमिट नहीं था। जब्त की गई नशीली दवाइयों की कुल कीमत करीब 18,300 रुपये आंकी गई है। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। शांतिनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ एनडीपीएस एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह नशीली सिरप कहां से लाई गई थी और किन-किन इलाकों में इसकी सप्लाई की जा रही थी। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी।

भिवंडी में 3.42 लाख की बिजली चोरी का खुलासा..

खाड़ीपार अहमद नगर रोड के मकान में अवैध कनेक्शन, आरोपी पर केस दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में खाड़ीपार, अहमद नगर रोड स्थित एक मकान में अवैध रूप से बिजली उपयोग किए जाने का बड़ा खुलासा हुआ है। टोरेंट पावर कंपनी की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले की शिकायत टोरेंट पावर कंपनी में एक्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत कु. अयुरी ओंकार परवारकर (27) ने 22 जनवरी को शांतिनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी उबैद मतीउल्लाह खान, जो अहमद नगर रोड, खाड़ीपार भिवंडी का निवासी है, ने अपने मकान में बिजली मीटर को बायपास कर सीधे अवैध कनेक्शन जोड़ रखा था। टोरेंट पावर की विजिलेंस टीम द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि आरोपी ने 10/2 स्क्वेयर एमएम के नीले रंग के केबल और दो कोर काले तार का उपयोग कर सीधे बिजली लाइन से कनेक्शन लिया था। इस अवैध व्यवस्था के जरिए लंबे समय से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी द्वारा कुल 10,159 यूनिट बिजली की चोरी की गई, जिससे टोरेंट पावर कंपनी को करीब 3,42,343.06 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। मामले की पुष्टि होने के बाद विजिलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और अवैध केबल तथा तार जब्त कर लिए। शांतिनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, हालांकि घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और आगे की जांच जारी है। लगातार सामने आ रहे बिजली चोरी के मामलों से टोरेंट पावर कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं टोरेंट पॉवर कंपनी ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध बिजली उपयोग से बचें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने 70वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 में वर्क्स एफिशिएंसी शील्ड एवं ट्रैक मशीन शील्ड प्राप्त की, सोलापुर मंडल के 9 रेलकर्मियों को असाधारण प्रदर्शन के लिए 'विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने 21 जनवरी 2026 को मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (एएसऊ) के मध्य रेल सभागार में आयोजित भव्य समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 98 व्यक्तियों को 70वां 'विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025' प्रदान किए, साथ ही विभिन्न मंडलों, कार्यशालाओं एवं स्टेशनों को 24 शील्ड भी सौंपी गईं।

इस समारोह में मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने वर्क्स एफिशिएंसी शील्ड एवं ट्रैक मशीन शील्ड अपने नाम की। ये शील्ड मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम), सोलापुर डॉ. सुजीत मिश्रा एवं उनकी टीम ने ग्रहण कीं। इसके अतिरिक्त महाप्रबंधक ने सोलापुर मंडल के 9 रेलकर्मियों को उनके सराहनीय और असाधारण प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 'विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार' से सम्मानित किया।

इस अवसर पर संबोधन करते हुए महाप्रबंधक ने अति विशिष्ट रेल सेवा

पुरस्कार 2025 के विजेताओं तथा हाल ही में नई दिल्ली में 5 शील्ड जीतने वाली मध्य रेल की टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड स्तर पर 5 शील्ड जीतना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

श्री गुप्ता ने कहा कि लोगों को रेलवे से बहुत अपेक्षाएँ हैं और इन्हें पूरा करने के लिए माननीय रेल मंत्री द्वारा सभी रेलकर्मियों के लिए कुछ प्रमुख उपाय निर्धारित किए गए हैं। इनमें वर्ष 2026 के लिए '52 सप्ताह में 52 सुधार' का लक्ष्य, यात्रियों, रेलकर्मियों तथा रेलवे संपत्ति और प्रणाली की सुरक्षा पर विशेष ध्यान, बदलते समय के अनुरूप प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं एआई को अपनाना, अनुरक्षण पद्धतियों का उन्नयन, प्रशिक्षण मानकों में सुधार एवं कौशल विकास पर फोकस तथा पुरानी सोच में सकारात्मक परिवर्तन शामिल हैं।

महाप्रबंधक ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें प्रधान विभागाध्यक्षों, मंडल रेल प्रबंधकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से युक्त सशक्त कार्यबल पर गर्व है। उन्होंने इस बार पुरस्कार प्राप्त न कर पाने वालों को भी प्रोत्साहित किया और समर्पण, टीमवर्क तथा साझा लक्ष्य के साथ कार्य करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार इस बात को सुदृढ़ करते हैं कि परिश्रम और समर्पण को महत्व दिया जाता है और उसकी सराहना होती है, जो निश्चित रूप से आगे चलकर सकारात्मक परिणाम देगा।

इस कार्यक्रम में अपर महाप्रबंधक श्री प्रतीक गोस्वामी, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री पी. पी. पांडे, सभी प्रधान विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक, मध्य रेल के अन्य अधिकारी, मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा एवं कार्यकारिणी सदस्याएं तथा मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समारोह से पूर्व मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पूरे कार्यक्रम का यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया तथा जनसंपर्क विभाग द्वारा लाइव प्रसारण देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

भारतीय का नया 'हिटमैन'! तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा बोले- अभी सुधार की गुंजाइश है

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कहा कि वह अपने आक्रामक अंदाज से पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नक्शेकदम पर चल रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वह अभी पूरी तरह परिपक्व हुए हैं। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला की शुरुआत की, जो आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले भारत की आखिरी द्विपक्षीय श्रृंखला थी। उन्होंने 35 गेंदों में 84 रन की सनसनीखेज पारी खेली, जिसमें पांच चौके और आठ छक्के शामिल थे। इस पारी की बदौलत भारत ने 238/7 का विजयी स्कोर बनाया। पिछले साल से ही अभिषेक शानदार फॉर्म में हैं और 22 मैचों और पारियों में 44.90 के औसत और 196.86 के स्ट्राइक रेट से 943 रन बना चुके हैं। इनमें एक शतक, छह अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 है। 'क्रिकेट लाइव' पर बात करते हुए अभिषेक ने अपनी बल्लेबाजी के बारे में कहा कि उन्हें अभी भी लगता है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं अभी पूरी तरह परिपक्व हो गया हूं, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा काम पहले छह ओवरों में आक्रामक क्रिकेट खेलना है। मैं इसके लिए काफी अभ्यास कर रहा हूं। मुझे पता है कि अगर मैं अच्छी शुरुआत दूं या शुरुआत में ही अच्छा इरादा दिखाऊं, तो टीम उस लय को बनाए रख सकती है। मैं हमेशा इसी बारे में सोचता हूं। उन्होंने भारत के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा के प्रभाव के बारे में भी बात की और कहा कि जब वह टीम में आए थे, तो कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर चाहते थे कि वह 'हिटमैन' की तरह ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाएं। उन्होंने कहा कि रोहित भाई ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पावरप्ले में उनकी शानदार शुरुआत की वजह से हमेशा दबाव बना रहता था। जब मैं टीम में आया, तो कोच और कप्तान मुझसे भी यही उम्मीद कर रहे थे। मुझे लगा कि यह मेरे खेलने के तरीके के अनुकूल भी है क्योंकि मुझे शुरुआती कुछ गेंदों से ही आक्रामक खेलना पसंद है। इसलिए, मुझे लगता है कि मैं रोहित भाई के नक्शेकदम पर चल रहा हूं, और मैं इस तरह से खेलकर भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करने से बहुत खुश हूं। अभिषेक ने कहा कि अगर उन्हें आक्रामक होकर खेलना है और अपना इरादा दिखाना है, तो वे अपने मैचों से पहले एक खास तरीके से अभ्यास करते हैं। उन्होंने कहा, 'जब मुझे एक हफ्ता या दस दिन मिलते हैं, तो मैं अगली सीरीज या मैचों में जिन गेंदबाजों का सामना करना है, उन्हें ध्यान में रखता हूं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मैं उन योजनाओं को कैसे अमल में लाता हूं। आगामी टी20 विश्व कप के लिए भी मैं अभ्यास कर रहा हूं। मुझे पता है कि हम पूरे भारत में अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग टीमों के खिलाफ खेलेंगे, इसलिए तैयारी बेहद जरूरी है।'

टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान का बड़ा दांव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर- शाहीन की वापसी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। यह सीरीज 29 जनवरी से शुरू होगी। आईसीसी की वेबसाइट के अनुसार, इस सीरीज में बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की अनुभवी जोड़ी टी20 सीरीज में वापसी कर रही है। बाबर और शाहीन बिग बैश लीग (बीबीएल) 2025-26 सीजन में खेलने के कारण जनवरी की शुरुआत में श्रीलंका में हुई पाकिस्तान की टी20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे।

शादाब खान के आने से पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी, जिसमें अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टी20 मैच खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मैच 29 जनवरी को, दूसरा मैच 31 जनवरी को और तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। तीनों मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीन मैचों की यह श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों के लिए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में काम करेगी, जो 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका में शुरू होगा। विश्व कप में पाकिस्तान ग्रुप 'ए' में अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड और सह-मेजबान भारत के साथ है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 'बी' में श्रीलंका, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ है। पाकिस्तान ने इसी महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेली थी। यह श्रृंखला ड्रॉ रही, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने एक-एक मैच जीता और एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला से पहले, पाकिस्तान ने अपने घरेलू मैदान पर टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की त्रिकोणीय श्रृंखला खेली थी, जिसमें श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान ने भाग लिया था। पाकिस्तान ने यह त्रिकोणीय श्रृंखला जीती थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए पाकिस्तान की टीमः सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक।

जनवरी में तेज हुई आर्थिक रफ्तार, एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट पीएमआई 59.5 पर पहुंचा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत के निजी क्षेत्र की गतिविधियों में जनवरी के महीने में मजबूती देखने को मिली है। एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स जनवरी में बढ़कर 59.5 पर पहुंच गया, जो दिसंबर में 57.8 था। नए कारोबार में तेज वृद्धि के चलते मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस–दोनों सेक्टरों की गतिविधियों में इजाफा हुआ है। यह जानकारी एस एंड पी ग्लोबल की ओर से संकलित और शुक्रवार को जारी पीएमआई रिपोर्ट में दी गई।

मौसम के अनुसार समायोजित इस इंडेक्स के मुताबिक उत्पादन में वृद्धि की रफ्तार हालांकि थोड़ी धीमी रही लेकिन जनवरी में निर्माण और सेवा–दोनों क्षेत्रों में लगभग समान गति से विस्तार दर्ज किया गया। यह इंडेक्स हर महीने इन दोनों सेक्टरों के कुल उत्पादन में बदलाव को दर्शाता है।

नए कारोबार में बढ़ोतरी ने निजी क्षेत्र की कुल गतिविधियों को मजबूती दी। कंपनियों ने बेहतर ग्राहक मांग और मजबूत मार्केटिंग रणनीतियों का फायदा मिलने की बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माण कंपनियों ने सर्विस सेक्टर की तुलना में अपनी बिक्री में ज्यादा तेजी दर्ज की।

जनवरी में अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर में भी साफ इजाफा देखने को मिला, जो पिछले चार महीनों में निर्यात की सबसे तेज वृद्धि रही। भारतीय कंपनियों को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व से ज्यादा ऑर्डर मिले, जिससे कुल कारोबारी गतिविधियों को और मजबूती मिली। निजी क्षेत्र में जनवरी के दौरान भर्ती में भी इजाफा हुआ, जबकि दिसंबर में यह स्थिर रही थी। नौकरियों में बढ़ोतरी भले ही सीमित रही, लेकिन यह लंबे समय के औसत ट्रेंड के अनुरूप है। कंपनियों ने कमर्शियल जरूरतों के हिसाब से खासतौर पर जूनियर और मिड-लेवल कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाई।

पीवी सिंधू और लक्ष्य सेन हारे, इंडोनेशिया मास्टर्स में भारतीय चुनौती समाप्त

जकार्ता। पीवी सिंधू और लक्ष्य सेन अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में सीधे गेम में हारकर बाहर हो गये जिससे पांच लाख डॉलर पुरस्कार राशि वाले इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती शुक्रवार को समाप्त हो गई।

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधू को महिला एकल क्वार्टर फाइनल में चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व नंबर चार खिलाड़ी चेन यू फेई के खिलाफ 42 मिनट तक चले मुकाबले में 13-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही सिंधू का सुपर 500 स्तर के इस टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया। चेन यू फेई के खिलाफ आमने-सामने के रिकॉर्ड में अब सिंधू 6-8 से पीछे हो गई हैं। सिंधू की चीन की इस खिलाड़ी के खिलाफ पिछली जीत वर्ष 2019 में दर्ज हुई थी। पुरुष एकल में 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन को थाईलैंड के उभरते खिलाड़ी पनिचाफोन तीरारत्साकुल से कड़े मुकाबले में 18-21, 20-22 से हार मिली। यह मैच 46 मिनट तक चला। लक्ष्य दोनों गेम में कड़ी टक्कर देने के बाद भी जीत दर्ज करने में नाकाम रहे। लक्ष्य को हराने से पहले थाईलैंड का 21 साल कर यह खिलाड़ी प्री-क्वार्टरफाइनल में मलेशिया के पेरिस ओलंपिक 2024 के कांस्य पदक विजेता ली जी जिया को भी टूर्नामेंट से बाहर कर चुका है।

पाकिस्तानी क्रिकेटर ने किया आईसीसी का समर्थन, बांग्लादेश को दी सख्त चेतावनी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव अब वैश्विक क्रिकेट बहस का विषय बन गया है। भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर चुके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के फैसले पर जहां अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के रुख का खुलकर समर्थन किया है। कनेरिया का मानना है कि अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटता है, तो इससे टूर्नामेंट की गुणवत्ता या आईसीसी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दानिश कनेरिया ने साफ कहा कि आईसीसी का यह फैसला बिल्कुल सही है कि तय शेड्यूल में आखिरी समय पर बदलाव नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में यात्रा योजना, वेन्यू, सुरक्षा व्यवस्था और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी तैयारियां पहले से तय होती हैं। ऐसे में किसी एक टीम की मांग पर पूरा ढांचा बदलना व्यावहारिक नहीं है।बांग्लादेश ने भारत के साथ बिगड़े राजनीतिक संबंधों और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आईसीसी से अनुरोध किया था कि उसके सभी मैच श्रीलंका में कराए जाएं। हालांकि, आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि टूर्नामेंट पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही भारत में आयोजित होगा। इस फैसले को आईसीसी बोर्ड की बैठक में अधिकांश सदस्य देशों का समर्थन मिला, जहां सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश के पक्ष में वोट दिया।

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
सिगनल एवं दूरसंचार कार्य

ई–निविदा सूचना (Re-Invitation)
निविदा सूचना संख्याः सोला–एन–टी–2025–26–40 दिनांकः– 22.01.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से डी.आर.एम. (एस एंड टी) कार्यालय, मध्य रेलवे, सोलापुर निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई–निविदाएं आमंत्रित करता हैः **क्र सं.:–** 1., **काम का नामः–** मध्य रेलवे के सोलापुर डिवीजन में विभिन्न माल गोदामों और चैजिंग रूम के विकास के लिए FOIS नेटवर्क सहित दूरसंचार सुविधा का प्रावधान / स्थानांतरण करना।, **निविदा संख्याः–** सोला–एन–टी–2025–26–40, **कार्य की अनुमानित लागतः–** Rs.1,22,45,668.66, **टेंडर फॉर्म की कीमतः–** NIL, **जमा की जाने वाली धरोहर राशिः–** Rs.2,11,200.00, **कार्य पूर्ण करने की अवधिः–** 8 महीने, निविदा बंद होने का समय एंव दिनांक **www.ireps.gov.in** पर 16.02.2026 at 15.30 Hrs. विवरण ireps वेबसाइट में उपलब्ध हैं। शुद्धिपत्र/संशोधन यदि कोई हो तो केवल उपरोक्त ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। केवल ऑनलाइन निविदाएं ही स्वीकार की जाएंगी। मैनुअल/डाक/ई–मेल, कैक्स, हस्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे कंपनी के नाम के साथ तृतीय श्रेणी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करें और इसे **www.ireps.gov.in** पर पंजीकृत करें। बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान नेट बैंकिंग या पेमेंट गेटवे के माध्यम से या बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जाएगा और मूल बैंक गारंटी निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नामित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि से पहले (अर्थात बोलियों जमा करने की अंतिम तिथि को छोड़कर) जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया **www.ireps.gov.in** देखें।

मंडल रेल प्रबंधक, सिगनल एवं दूरसंचार
10 सोलापूर

टिकट के लिए RailOne App डाउनलोड करे

क्या युजवेंद्र चहल और आरजे महविश की दोस्ती में आई दरार? इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को किया 'अनफॉलो'

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन हाल ही में आई एक खबर ने उनके प्रशंसकों को चौंका दिया है। खबर है कि युजवेंद्र चहल और मशहूर कंटेंट क्रिएटर आरजे महविश ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को 'अनफॉलो' कर दिया है। इस खबर का खुलासा बुधवार को मशहूर पैपराजी हैंडल वरिंदर चावला ने किया। रिपोर्ट के अनुसार, चहल और महविश पहले एक-दूसरे को फॉलो करते थे और अक्सर एक-दूसरे के पोस्ट पर चर्चा में रहते थे। हालांकि, अब दोनों की फॉलोइंग लिस्ट से एक-दूसरे का नाम नदारद है, जिसका मतलब है कि उन्होंने ऑनलाइन दुनिया में अपना कनेक्शन तोड़ लिया है।

हालांकि चहल और महवश के एक-दूसरे को अनफॉलो करने के पीछे की वजह अभी पता नहीं चली है, लेकिन नेटिज़न्स संभावित नतीजों को लेकर अटकलें लगा रहे हैं।

जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि चहल और महवश का रिश्ता हमेशा से अटकलों का विषय रहा है, खासकर 2025 में क्रिकेटर के धनश्री वर्मा से तलाक के बाद। चहल और महवश के बीच संभावित रोमांस की अफवाहें फैल रही थीं, जिसमें कई लोगों को शक था कि वे सिर्फ दोस्त से कहीं ज़्यादा हैं। दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता था, जिससे यह चर्चा और तेज़ हो गई। हालांकि, युजवेंद्र और महवश ने हमेशा यही कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पिछले साल अपने 'राइज एंड फॉल' के दौरान, धनश्री ने चहल से अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए कहा था, 'भले ही मैंने उसे बदलते हुए देखा, मैंने उस पर और रिश्ते पर भरोसा किया। मेरी समस्या यह है कि मैं अपने आस-पास के लोगों को बहुत ज़्यादा मौके देती हूं। लेकिन आखिरकार, मैं इससे थक गई। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश की और अपना सौ प्रतिशत दिया। मैं हमेशा उसके लिए चिंतित रहूंगी; इसकी मैं गारंटी दे सकती हूं।'

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
ई–प्रोक्योरमेंट

संख्या **SUR/Sr.DMM/T.No.96255853**
दिनाकः 22.01.2026 ई–टेंडर नोटिस

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मंडल स्टोर कार्यालय मध्य रेलवे, सोलापुर, निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई–निविदाएं आमंत्रित करता है। **01. टेंडर नंबरः– 96255853, 02. विवरणः–** संलग्न अनुलग्नक–ए में विनिर्देशों के अनुसार हल्के वजन के लिथियम बैटरी टैंपिंग मशीन के एक सेट की सप्लाई, इनस्टॉलेशन और कमिशन करना, जिसमें 2 टैंपर शामिल हैं। (8 बैटरियां, 4 चार्जर, 4 टैंपिंग टूल, 2 परिवहन ट्रॉली सहित), **03. मात्राः– 29 Set., 04. बयाना राशि (INR):–** Rs. 468130.00, **www.ireps.gov.in** पर निविदा बंद होने की तिथि और समयः– 09.02.2026 11:30 बजे के बाद, संभावित निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा समाप्ति की तिथि से पहले वेबसाइट पर बार–बार विजिट करते रहें ताकि इस निविदा के लिए जारी किए गए किसी भी परिवर्तन/शुद्धिपत्र पर ध्यान दिया जा सके। वेबसाइटः **www.ireps.gov.in.**

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक
08 सोलापूर

टिकट के लिए RailOne App डाउनलोड करे

पश्चिम रेलवे
वडोदरा मंडल

सेवा भवन का प्रावधान

ई-निविदा सूचना सं.DRM-BRC 169 वर्ष 2025-26 भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (का/ले) वडोदरा द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **निविदा संख्या और कार्य का नाम: DRM BRC 169 वर्ष 2025-26** एएनएनडी-जीडीए अनुभाग पर नॉन इंटरलॉक्ड एलसी गेट नंबर 3,21,27 और 32 की इंटरलॉकिंग के संबंध में सेवा भवन का प्रावधान और एडीईएन-एनडी के अधिकार क्षेत्र के तहत प्लेटफॉर्म कवर-शेड और वैली गटर में सुधार। **कार्य की अनुमानित लागत (रुपये में):** ₹ 1,89,38,504.27 **जमा की जाने वाली बोली सुरक्षा (रुपये में):** ₹ 2,44,700.00 **निविदा जमा करने और निविदा खोलने की तिथि और समय:** निविदा 12.02.2026 को 15.00 बजे से पहले जमा की जानी है, और उसी तिथि को 15.30 बजे खोली जानी है। **वेबसाइट का विवरण और उस जगह का नोटिस जहाँ पूरी डिटेल्स देखी जा सकती हैं और उस ऑफिस का पता जहाँ से निविदा फॉर्म खरीदा जा सकता है:** डिविजनल रेलवे मैनेजर (का/ले) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-4 **वेबसाइट www.ireps.gov.in**

BRC 331

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पूर्वोत्तर रेलवे
Email-dycmmgkpd@gmail.com
Website- www.ner.indianrailways.gov.in & www.tendrs.gov.in

निविदा सूचना संख्या–15 दिनांक–16.01.26 ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा आमंत्रण उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर कृते भारत के राष्ट्रपति तथा उनकी ओर से ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। सामग्री का का पूर्ण विवरण तथा नियम एवं शर्ते वेबसाईट **www.ner.indianrailways.gov.in & www.tendrs.gov.in** पर देखा जा सकता है। क्र0सं0 1:– निविदा संख्या एवं खुलने की तिथिः 10257909 dt.16.02.26, मद का सक्षिप्त विवरणः सप्पलाई, इंस्टालेशन एडं कमीशनिंग ऑफ CNC एक्सल टर्निंग लेथ इत्यादि। मात्राः 01 No. अर्नेस्ट मनी(रूपया): 11,91,000/– 1. उपरोक्त निविदा आईआरईपीएस के साइट http/www.ireps.gov.in पर स्थित है। जो पतिष्ठान इलेक्ट्रानिकली पंजीकृत है वे ई–टेण्डर में सम्मिलित हो सकते हैं। जो प्रतिष्ठान क्लास 3 डिजिटल सर्टिफिकेट नही प्राप्त किये है वे अधिकृत एजेन्सी जो भारत सरकार के द्वारा अधिकार पत्र आईटी अधिनियम 2000 से अधिकृत है उनसे प्राप्त कर सकते है। मैन्युअल निविदा स्वीकृत नही की जायेगी। 2– आपूर्तिकर्तागण को यह सूचित किया जाता है कि उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर विज्ञापित निविदाएं एवं सभी बलेटिन निविदाएं केवल ईपीएस (ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम) द्वारा खोली जा रही है, जो भी प्रतिष्ठान उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की निविदाओं के प्रति इच्छुक हो एवं भाग लेना चाहते हो उन्हे आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा एवं अपने प्रतिष्ठान को CRIS / NEW DELHI में पंजीकृत कराना होगा। इस सम्बंध में आवश्यक विस्तृत विवरण वेबसाइट **http//www.ireps.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है। 3–निविदा सूचना के अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रकाशन में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी प्रकाशन मान्य होगा। 4–एलोकेशन शीर्ष निविदा प्रपत्र, जमानती धनराशि का 00844517 तथा बयाना धनराशि का 00084506 हैं। उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ई० निविदाओं का टेण्डर काष्ट तथा ईएमडी का भुगतान ऑन–लाइन IREPS PORTAL पर ही मान्य होगा जो दिनांक – 01/09/2016 से या उनके बाद प्रकाशित निविदाओं पर प्रभावी होगा । यह Global tender पर प्रभावी नही होगा।

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो
मुजाधि/एस–76 गोरखपुर

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

अनुष्का ने विराट कोहली को खिलाए दिल्ली वाले छोले-भटूरे

दुबई की चमकती लोकेशन्स, प्यार भरी नोंक-झोंक और सरप्राइज से भरा एक खास पलष्ठ अनुष्का शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह है दोनों का एक नया

रोमांटिक अंदाज, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है। कभी हल्की-फुल्की प्रतिस्पर्धा तो कभी मुस्कानें बिखेरते निजी पल, इस पूरे अनुभव में कपल की केमिस्ट्री साफ झलकती है। खास बात यह रही कि अनुष्का ने विराट के लिए कुछ ऐसा प्लान किया, जिससे उनके चेहरे पर बचपन वाली खुशी लौट आई। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की केमिस्ट्री हमेशा फैंस को दीवाना बनाती है। अब दोनों ने दुबई टूरिज्म को प्रमोट करने वाले एक नए रोमांटिक ऐड में दिल जीत लिया है। गुरुवार को विराट और अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर यह ऐड शेयर किया, जिसमें वे एक-दूसरे को सरप्राइज देने की स्वीट कॉम्पिटिशन में नजर आए। एड की शुरुआत दुबई के खूबसूरत नजारों से होती है, जहां विराट अनुष्का को चुनौती देते हैं कि वह उन्हें सरप्राइज दें। इसके जवाब में अनुष्का दुबई के रेगिस्तान के बीचों-बीच एक प्राइवेट लंच डेट प्लान करती हैं। इसके बाद दोनों वाइल्डलाइफ साइटसीइंग और बीच पर मस्ती करते नजर आते हैं। बीच पर खेले गए वॉलीबॉल मैच में अनुष्का विराट को हरा देती हैं और हंसते हुए कहती हैं, 'मैं बेहतर एथलीट हूं।' इस पर विराट मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं, 'और मैं बेहतर डांसर हूं'।

पश्चिम रेलवे
वडोदरा मंडल

इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम का व्यापक वार्षिक रखरखाव

निविदा सूचना संख्याः S&T/BRC/25-26/15/SIG तारीखः 19-01-2026 भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए सीनियर D S T E / वडोदरा निविदा संख्या SandT_BRC_25-26_33_SIG के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते हैं। बोली लगाने वाले अपनी ओरिजिनल/रिवाइज्ड बोलियां सिर्फ क्लोजिंग तारीख और समय तक ही जमा कर पाएंगे। इस टेंडर के लिए मैनुअल ऑफर की अनुमति नहीं है, और ऐसा कोई भी मैनुअल ऑफर मिलने पर उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। **1. कार्य का नाम और उसका स्थानः** वडोदरा मंडल मे तीन साल के लिए इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम (स्टेटकॉन मेक) का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध। **2. कार्य की अनुमानित लागतः** 1,84,86,191.52 रुपये **3. जमा की जाने वाली बयाना राशिः** 2,42,400.00 रुपये **4. ई-निविदा जमा करने और ई-निविदा खोलने की तारीख और समयः** 13-02-2026 @ 15:00 बजे और 13-02-2026 @ 15:30 बजे **5. वेबसाइट की जानकारी और नोटिस का स्थान जहां पूरी जानकारी देखी जा सकती है आदिः** सीनियर डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, दूसरी मंजिल-एनेक्स बिल्डिंग, D R M ऑफिस, पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390004 **http://www.ireps.gov.in** **BRC 330**

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

ट्रेन संख्या 22962/22961

अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद

वंदे भारत एक्सप्रेस

को अस्थायी रूप से चार अतिरिक्त कोचों के साथ बढ़ाया जाएगा

तथा यह 26.01.2026 से 07.03.2026 तक 20 कोचों के रेक के साथ संचालित की जाएगी।

ठहराव के समय तथा कोच संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएँ।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in

Like us & Follow us on:
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी रिज़र्व टिकटों के लिए ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ रखें।

स्टार्टअप कंपनियों की बजट में कर छूट समयसीमा बढ़ाने, पूंजीगत लाभ कर में राहत की मांग

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने आगामी बजट में कर छूट समयसीमा बढ़ाने और पूंजीगत लाभ कर में राहत की मांग की है। उनका कहना है कि इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और कर बचत से मिली राशि का उपयोग कारोबार विस्तार एवं प्रौद्योगिकी निवेश में किया जा सकेगा। उद्योग जगत का कहना है कि वित्त वर्ष 2025-26 से सभी निवेशकों के लिए 'एंजेल टैक्स' को पूरी तरह खत्म किए जाने की घोषणा से निवेश माहौल में सुधार हुआ है। हालांकि अब स्टार्टअप और निवेशकों को खासकर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पूंजीगत लाभ कर में भी राहत की जरूरत है।

एंजेल टैक्स वह कर है, जो स्टार्टअप को उसके शेयर के उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर निवेश मिलने की स्थिति में उस अतिरिक्त राशि पर लगाया जाता है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप 'एआसोक' के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रवीण सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत किए गए सुधारों ने मजबूत आधार तैयार किया है और आगामी बजट इन सुधारों को

जमीनी स्तर पर लागू करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि एंजेल टैक्स हटने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और अब विदेशी निवेशकों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है, जिस पर वर्तमान में करीब 12.5 प्रतिशत कर लगता है। सिंह ने कहा कि इससे शिक्षा जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में वैश्विक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

स्टार्टअप में निवेश से होने वाले लाभ पर पूंजीगत लाभ कर लगता है, जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक होता है। यदि शेयर 24 महीने से कम समय में बेचे जाते हैं, तो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (एसटीसीजी) लगता है, जबकि 24 महीने से अधिक समय पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लागू होता है। इसके अलावा, उद्योग जगत आयकर कानून की धारा 80-आईएसी के तहत डीपीआईआईटी से मान्यता-प्राप्त स्टार्टअप को होने वाले लाभ पर 100 प्रतिशत आयकर छूट की समय-सीमा को बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। यह छूट कंपनी के शुरुआती 10 वर्षों में किसी भी लगातार तीन वर्षों के लिए उपलब्ध होती है लेकिन वर्तमान में इसकी पात्रता एक अप्रैल 2030 तक सीमित है। स्टार्टअप चाहते हैं कि इसे 2032 या 2035 तक बढ़ाया जाए।

निर्माण क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप 'पावरप्ले' के सह-संस्थापक एवं सीईओ ईश दीक्षित ने कहा कि एंजेल टैक्स का हटना शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए अहम कदम है, लेकिन विदेशी निवेश से जुड़े पूंजीगत लाभ कर को लेकर अभी भी स्पष्टता और राहत जरूरी है। सेवा क्षेत्र के स्टार्टअप 'यूक्लीन' के संस्थापक एवं सीईओ अरुणाभ सिन्हा ने कहा कि सेवा आधारित और परिसंपत्ति-प्रधान स्टार्टअप फर्मों के लिए किफायती ऋण तक बेहतर पहुंच जरूरी है।

एसईसी कार्रवाई की खबर से अडानी ग्रुप के शेयर क्रैश, 14 फीसदी तक लुढ़के स्टॉक

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। औद्योगिक समूह अडानी ग्रुप के शेयरों में शुक्रवार को भारी बिकवाली देखने को मिली। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की खबर के बाद ग्रुप की प्रमुख कंपनियों के शेयर 14 फीसदी तक टूट गए। गिरावट के चलते अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप एक ही दिन में करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए घटकर 12.45 लाख करोड़ रुपए रह गया।

सबसे ज्यादा दबाव अडानी ग्रीन एनर्जी पर देखने को मिला, जिसके शेयर 14.14इ गिरकर 776.40 रुपए पर आ गए। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 9इ से ज्यादा टूटकर 1, 886.80 रुपए पर पहुंच गए, जो इसका 52 हफ्ते का निचला स्तर है। वहीं, अडानी एनर्जी के शेयर 11इ गिरकर 822.15 रुपए, जबकि अडानी पोर्ट्स के शेयर करीब 8इ फिसलकर 1, 295.40 रुपए पर आ गए। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट, एसीसी और अडानी टोटल गैस समेत ग्रुप की अन्य कंपनियों के शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली।

अमेरिकी रेगुलेटर एसईसी ने एक अमेरिकी अदालत से अनुमति मांगी है कि वह अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को सीधे ईमेल के जरिए समन भेज सके। एसईसी ने कोर्ट को बताया कि भारत ने पहले दो मौकों पर आधिकारिक चैनलों के जरिए समन भेजने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। एसईसी का कहना है कि मौजूदा तरीकों से समन भेजने में सफलता की संभावना कम है, इसलिए ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की मंजूरी मांगी गई है।

दिल्ली में कुदरत का यू-टर्न! तेज हवाओं और बारिश ने थामी रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। राजधानी दिल्ली में मौसम अचानक करवट ले लिया है। देर रात से चल रही तेज हवाओं और सुबह हुई बारिश ने आम लोगों के लिए नई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। राजधानीवासियों को सुबह दफ्तर या जरूरी कामों के लिए निकलना मुश्किल हो गया, वहीं ठंड का असर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अभी तक ठंड से राहत के संकेत नहीं दिए हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम और नमी के साथ तापमान में गिरावट की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 29 जनवरी के बीच उत्तर भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। विशेषकर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से इन क्षेत्रों का तापमान और भी कम हो जाएगा, जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है। हालांकि, विभाग ने साफ किया है कि तापमान में गिरावट के बावजूद किसी भी उत्तर भारतीय राज्य में फिलहाल शीतलहर की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर-पश्चिमी राज्यों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना भी है। 24 जनवरी को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा 25 जनवरी को भी इन राज्यों में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। वहीं, 25 और 26 जनवरी को दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में भी भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश और कोहरे को ध्यान में रखते हुए सड़क पर सावधानी बरतें। ठंड और कम तापमान के कारण सुबह-शाम समय पर खासतौर पर सड़क पर गाड़ी चलाते समय या पैदल सफर करते समय सतर्क रहें। बिजली गिरने की संभावना वाले क्षेत्रों में लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। यह मौसम बदलाव दर्शाता है कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में उत्तर भारत और कुछ दक्षिणी राज्यों में तेज हवाओं, बारिश और घने कोहरे के चलते लोगों को मौसम के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।

गणतंत्र दिवस से पहले पन्नू की 'स्लीपर सेल' वाली धमकी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कसा शिकंजा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में अशांति फैलाने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (शत्रुता को बढ़ावा देना), 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप), 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य) और 61 (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पन्नू ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके 'स्लीपर सेल' ने राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी और डाबरी इलाकों में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए हैं। हालांकि, जांच के बाद, विशेष प्रकोष्ठ को पन्नू द्वारा बताए गए स्थानों पर अभी तक कोई भी खालिस्तान समर्थक पोस्टर नहीं मिला है।

दिल्ली पुलिस द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए जारी किए गए अलर्ट पोस्टरों में मोहम्मद रेहान नामक एक आतंकवादी की तस्वीर छपी थी, जो अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सदस्य है और दिल्ली का रहने वाला है। एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी की तस्वीर पहली बार पोस्टरों में शामिल की गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, मोहम्मद रेहान दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा वांछित आतंकवादी है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त कई आतंकी खतरों की सूचनाओं के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ और पूरे नई दिल्ली जिले में व्यापक, प्रौद्योगिकी-आधारित सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बैठने की जगहों का नाम भारतीय नदियों के नाम पर रखा गया है। मेहमानों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा तैनाती के पैटर्न में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

नई दिल्ली जिले के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त देवेश कुमार महाला के अनुसार, कर्तव्य पथ क्षेत्र में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों का एक व्यापक नेटवर्क लगा हुआ है, जो उन्नत चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से निगरानी की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि इस राष्ट्रीय दिवस पर लगभग 10, 000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और जमीनी स्तर पर नौ बार ब्रीफिंग आयोजित की जा चुकी है।

शिकारी खुद यहां शिकार हो गया! कैसी तकनीक खेल गया ईरान, हुआ बड़ा खुलासा

तेहरान। ईरान पिछले करीब 20-25 दिन से उबल रहा है। देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली हुसैनी खमेई के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप भी दखल दे चुके हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बाद मेक ईरान ग्रेट अगेन की बात करते हुए अमेरिका प्रदर्शनकारियों के साथ आ गया है। खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पर शेखियान प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। इसके बावजूद ईरान में कोई तख्ता पलट नहीं हो पाया है और अभी दूर-दूर तक इसके आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर ईरान पर बरसों से अमेरिकी सेंशंस नहीं होते तो आज ईरान की तरक्की और उसकी इजात, उसकी खोज, उसके आविष्कार दुनिया देखती। कहा तो यह भी जाता है कि आज भी ईरान में छोटी बड़ी ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की नजरों से छिपी हुई है। दुनिया सिर्फ ईरान की आर्म इंडस्ट्री और खासकर रिवर्स इंजीनियरिंग से वाकिफ है। लेकिन ईरान दुनिया का एकलौता इस्लामिक मुल्क होगा जिसने साइंस और मजहब दोनों को एक साथ बड़ी समझदारी से समन्वित किया और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद तो इस दिशा में जमकर काम हुआ। कहा जाता है कि उनके साइंटिस्ट ने ऐसीऐसी चीजें बना ली है जो अब तक दुनिया से छिपी हुई हैं। शायद इसी वजह से आरोप लगता है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के वैज्ञानिकों की जान के दुश्मन बने रहते हैं।

इस्लामिक रिपब्लिक में कर्बला वाले जज्बे के साथ-साथ अपने दुश्मन को तकनीक के मैदान में भी धूल चटाने की सलाहियत है। ईरान में महंगाई के खिलाफ हुए प्रदर्शन या मुजाहरे देखते ही देखते हिंसक होने लगे थे। तीन से 4 दिन में ईरान में आग ही आग थी और महंगाई से राहत दो के नारे इस्लामिक रेवोल्यूशन मुर्दाबाद में बदल गए। अमेरिका खुलकर सामने आया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा किसी भी प्रदर्शनकारी पर कारवाई हुई तो अमेरिका एक्शन लेगा। ईरान में सरकार भी भांप गई कि यह तो मामला ही कुछ और है। फिर इसराइल के पीएम बेंजामिन बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आ गया। 2026 की जनवरी ईरान में कत्लो गारत और बर्बादी लाई थी। दुनिया भर में ईरान के वीडियो दिखाए जा रहे थे। ईरान एक्शन में आया। एहतेजाज कर रहे लोगों पर काबू पाने के लिए देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों के लीडर और उनकी जड़ को तलाशने का अभियान चला।

ईरान में इंटरनेट और मोबाइल बंद कर दिए जाने पर सीआईए एक्टिव हुई और अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से राब्ता कायम किया गया संपर्क किया गया। स्टारलिंक कंपनी ने अपनी खास सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए ईरान में इंटरनेट की सप्लाई शुरू कर दी। ट्रंप ने खुद ऐलान किया कि ईरान में स्टारलिंक की नेट सुविधा है। प्रदर्शनकारी लगे रहें।

चीन के ऊपर मची खलबली, आसमान में अटकीं 238 जानें, 45 मिनट हवा में चक्कर काटता रहा प्लेन

बीजिंग। थाईलैंड से रूस जा रहे अजूर एयर के एक बोइंग 757 विमान में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब पालयट ने अचानक से 'डिस्ट्रेस सिग्नल' (आपातकालीन संकेत) जारी कर दिया है। इस समय पर विमान में 238 यात्री मौजूद थे। गनीमत यह रही कि विमान को सुरक्षित रूप से चीन के लान्झू एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है।

सामने आई जानकारी के अनुसार विमान ने थाईलैंड के फुकेत से उड़ान भरी थी। सफर के करीब 4 घंटे बीतने के बाद विमान के चीनी हवाई क्षेत्र में आते ही अचानक पायलट को किसी तकनीकी गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। इसके चलते सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पायलट ने तुरंत इमरजेंसी कोड एक्टिवेट किया।

लान्झू एयरपोर्ट के पास पहुंचने पर विमान को तुरंत लैंड नहीं कराया गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, विमान करीब 45 मिनट तक होल्डिंग पैटर्न में चक्कर काटता रहा। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसा आमतौर पर ईंधन कम करने या रनवे पर आपातकालीन तैयारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अंततः, विमान ने रनवे 19 पर सुरक्षित लैंडिंग की।

विमान के उतरने से पहले लान्झू एयरपोर्ट प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। लैंडिंग के लिए रनवे को पूरी तरह खाली करा लिया गया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, मेडिकल एम्बुलेंस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर तैनात रहीं। एयरलाइन ने पुष्टि की है कि सभी 238 यात्री सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 769 अंक फिसला, निफ्टी 25, 048 के स्तर पर हुआ बंद

मुंबई। एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार (23 जनवरी) को बढ़त के साथ खुले लेकिन शुरुआती तेजी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कारोबार के दौरान बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला और बाद में बिकवाली हावी हो गई। वैश्विक तनाव के बीच निवेशकों की सतर्कता, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में कमजोरी तथा अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट ने

बाजार सेंटीमेंट को कमजोर किया।

बीएसई सेंसेक्स 769.67 अंक या 0.94 फीसदी की गिरावट के साथ 81, 537.70 के स्तर पर आ गया। इसी तरह, निफ्टी 241.25 अंक या 0.95 फीसदी टूटकर 25, 048.65 के स्तर पर बंद हुआ।

बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा। वहीं, अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट ने भी निवेशकों के सेंटीमेंट पर नकारात्मक असर डाला।

ग्लोब कैपिटल मार्केट्स में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च के सहायक उपाध्यक्ष विपिन कुमार ने कहा कि दो दिन की राहत रैली के बाद अडानी ग्रुप और बैंकिंग-फाइनेंशियल शेयरों में भारी गिरावट के चलते निफ्टी पर फिर से बिकवाली का दबाव बन गया है। उन्होंने बताया कि चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी नकारात्मक है और निफ्टी लोअर हाई-लोअर लो पैटर्न में कारोबार कर रहा है। फिलहाल 24, 900-24, 800 के स्तर पर सपोर्ट, जबकि 25, 500 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है।

दावोस में जेलेंस्की का यूरोप पर तीखा हमला, रूस के खिलाफ कमजोर प्रतिक्रिया पर जताई नाराजगी

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बृहस्पतिवार को अपने यूरोपीय सहयोगियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रूस के लगभग चार साल पहले किए गए आक्रमण और उसकी लगातार जारी अंतरराष्ट्रीय आक्रामकता के प्रति यूरोप की प्रतिक्रिया धीमी, बिखरी हुई और अपर्याप्त रही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने यूरोप के खिलाफ कई शिकायतें कीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की शांति पहल के बीच यूक्रेन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा, ''यूरोप भटका हुआ दिखता है।'' उन्होंने इस महाद्वीप से वैश्विक शक्ति बनने का आग्रह किया। उन्होंने यूरोप की प्रतिक्रिया की तुलना वेनेजुएला और ईरान में वाशिंगटन के साहसिक कदमों से की। पूर्व हास्य अभिनेता जेलेंस्की ने फिल्म 'ग्राउंडहॉग डे' का जिक्र किया, जिसमें मुख्य किरदार को एक ही तरह की दिनचर्या बार-बार जीनी पड़ती है। वह जो भी करे, अगला दिन नया नहीं आता और सब कुछ फिर उसी जगह से शुरू हो जाता है।

उन्होंने कहा, ''पिछले साल दावोस में मैंने अपने भाषण का अंत इस बात से किया था कि यूरोप को पता होना चाहिए कि वह खुद की रक्षा कैसे करे। एक साल बीत गया और कुछ नहीं बदला। मैं आज भी वही बात कह रहा हूं।'' जेलेंस्की ने यह भाषण दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करीब एक घंटे तक बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद दिया। ट्रंप ने बातचीत को ''बहुत अच्छा'' बताया और जेलेंस्की ने इसे ''सार्थक'' कहा। यूरोपीय देशों ने कीव को आर्थिक, सैन्य और मानवीय सहायता तो दी है, लेकिन 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के सभी सदस्य इसमें समान रूप से साथ नहीं हैं। रूस के प्रति नीति को लेकर यूरोप के भीतर मतभेद और कई बार धीमी प्रतिक्रिया से यूक्रेन निराश रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सीधी चेतावनी, मध्य पूर्व की ओर निकला अमेरिकी नौसैनिक का जंगी बेड़ा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का एक नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की हत्या और परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की संभावना को लेकर तेहरान को चेतावनी दोहराई है। ट्रंप की ये टिप्पणियां गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच से लौटने के दौरान आईं। ये टिप्पणियां ईरान में आंतरिक अशांति और परमाणु गतिविधियों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच की स्थिति को दर्शाती हैं।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स से नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों के आने वाले दिनों में मध्य पूर्व पहुँचने की उम्मीद है। क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं और ठिकानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियों पर भी विचार किया जा रहा है, जो वाशिंगटन के मजबूत सैन्य विकल्पों को रेखांकित करता है। ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि हमारे कई जहाज उस दिशा में जा रहे हैं, एहतियात के तौर पर... मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि इस तैनाती का उद्देश्य ईरानी कार्रवाइयों को रोकना था और अमेरिका को शायद इसका इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दोहराई और कहा कि अगर ईरान ने संवर्धन गतिविधियां फिर से शुरू कीं तो अमेरिका दोबारा कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा दोबारा करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें किसी और क्षेत्र में जाना होगा। हम वहां भी उन पर उतनी ही आसानी से हमला करेंगे। उन्होंने यह दावा भी दोहराया कि उनकी धमकियों के बाद ईरान ने प्रदर्शनकारियों की लगभग 840 नियोजित फांसी रोक दी। ट्रम्प ने कहा कि मैंने कहा था अगर तुम उन लोगों को फांसी देते हो, तो तुम्हें अब तक की सबसे भीषण मार पड़ेगी।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)